HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 01-15 दिसम्बर, 2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 2, अंक 34/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

www.therievtimes.com

हमारे विचार ही हमारे वातावरण का निर्माण करते है..... डॉ0 एल सी शर्मा

THE ONLY INITIATIVE THAT COVERS ALL 17 SDG's GOALS

द रीव टाइम्स को सामाजिक विकास में हासिल हुआ बड़ा मुक़ाम...

ए बी पी न्यूज़ ब्रांड ऐक्सिलेंस पुरस्कार से मुंबई में हुआ सम्मानित / कम समय में ही जनता की आवाज़ बन गया है समाचार पत्र

द रीव टाइम्स, ब्यूरो

द रीव टाइम्स को अभी प्रकाशन का एक वर्ष ही हुआ है और इस पाक्षिक समाचार पत्र ने अपनी निष्पक्ष ख़बरों, लेखों, गुणवत्ता और पारदर्शिता के कारण पाठकों में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। एक वर्ष के पूरा होने पर द रीव टाइम्स ने पाठकों और समालोचकों की कार्यशाला आयोजित की थी। इस बीच अब द रीव टाइम्स को एक और बुलंदी तब हासिल हुई है जब राष्ट्रीय समाचार चैलन एबीपी ने इसे सामाजिक विकास में सेवाओं हेतु ब्रांड ऐक्सिलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार **एबीपी न्यूज़ अवार्ड** सेरेमनी में मुंबई के ताज़ लैंड्स एंड में प्रदान किया गया। पुरस्कार को द रीव टाइम्स के प्रधान संपादक डॉ० एल सी शर्मा ने प्राप्त किया। इस अवसर पर उनके साथ आईआईआरडी निदेशक सुषमा शर्मा, आईआईआरडी के सह-निदेशक रविकांत वावगे और फ्लायर ग्रुप के सीईओ आन्नद नायर के अलावा एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह पुरस्कार सामाजिक विकास में द रीव टाइम्स प्रकाशन की ओर से प्रदान की गई बेहतरीन व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। गौरतलब है कि पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स ने सामाजिक विकास की ख़बरों और विविध लेखों के साथ पाठकों तक पहुंचने का प्रयास तो किया ही है साथ ही सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और योजना/परियोजनाओं को भी घर-घर तक सरल तरीके से उपलब्ध करवाने में सहयोग दे रहा है। इस समाचार पत्र में प्रत्येक वर्ग के लिए पठन सामग्री उपलब्ध है। विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान, रोज़गार के लिए करियर संबन्धि जानकारी, कानून की जानकारी, स्वास्थ्य संबन्धि जानकारी, आईआईआरडी और मिशन रीव की विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं और कार्यक्रमों के अलावा प्रदेश, देश और दुनिया की पाक्षिक ख़बरों का आईना है। द रीव टाइम्स के प्रधान संपादक डॉ० एल सी शर्मा ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बताया कि कम समय में लोगों के दिलों में स्थान पाकर द रीव टाइम्स ने यह साबित किया है कि निष्पक्ष और खोजी पत्रकारिता जनता की आवाज़ बनती है। यह पुरस्कार उन सभी पाठकों

और समालोचकों को समर्पित है जिन्होंने इस समाचार पत्र को समय-समय पर प्रेरणास्रोत के रुप में सेवाऐं दी हैं। साथ ही उन्होंने द रीव टाइम्स की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा और सच को द रीव टाइम्स लोगों तक पहुंचाता रहेगा साथ ही राष्ट्र निर्माण में सेवाऐं जारी रहेंगी।

समाचार पत्र को कम समय में ही खूब सराहना मिल रही है तथा एबीपी न्यूज़ का यह एक्सीलेंसी पुरस्कार एक प्रोत्साहन की तरह है जो निरंतर निष्पक्ष और सटीक लेखन के लिए प्रेरणा देता है। जनता की आवाज़ बनने का निरंतर प्रयास जारी रहेगा.

... प्रधान संपादक

पराली के समाधान को आगे आया आईआईआरडी

द रीव टाइम्स, ब्यूरो

फसलों के तैयार होने के बाद खेतों में बचने वाली पराली आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पराली के सही निस्तारण की व्यवस्था न होने के कारण किसान इसे जलाने को मजबूर हैं तो उनकी यह मजबूरी दिल्ली और साथ लगते दूसरे राज्य के लोगों को लिए जान की आफत बन गई है।

पराली की इस गंभीर समस्या से पार पाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान (आईआईआरडी) शिमला एक पहल की है। शुरूआत की गइ उन विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के साथ जो पराली की समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के सेक्टर-18 में टैगोर थियेटर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आगाज आईआईआरडी के चेयरमैन प्रो. आरके गुप्ता ने दीप प्रजवलित कर किया। इस दौरान आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉ. एलसी शर्मा, निदेशक सुषमा शर्मा, फ्लायर ग्रुप के सीईओ आनन्द नायर, रीव क्लीनिक हैड डा. केआर शांडिल, आईएफटीआई के सीईओ रंजन मोहंती, कंपनी सचिव अभिमन्यु कंवर व अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कई नामी विशेषज्ञों ने पराली की समस्या से निपटने को लेकर अपने विचार रखें। इस दौरान जाने-मानें और विख्यात कृषि विशेषज्ञ श्री एमएस स्वामीनाथ ने पराली समस्या से निपटने संबंधि सुझावों को ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से किसानों और वक्ताओं के साथ साझा किया।उन्होंने कहा कि पराली से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इससे टाइल्स, कागज और जरूरत का अन्य सामान बनाया जा सकता है। इसके लिए किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है।

आईआईआरडी चेयरमैन प्रो. आरके गुप्ता ने कहा कि आज पर्यावरण को बचाने के लिए गंभीरता से सोचने की जरूरत है ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सुरक्षित कर सके। इसी कड़ी में सीएसआर विजन निदेशक डॉक्टर दीपक पांडया ने कहा कि पराली जलाना उससे निजात पाने का आसान तरीका तो है लेकिन इस तरीके से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि किसान धरती पुत्र है और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे में किसानों को ही इस समस्या से निपटने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को प्राथमिकता के आधार पर पराली से निपटने के लिए नई तकनीक को अपनाने में आगे आना चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के पूर्व चेयरमैन प्रो.एस अहलुवालिया ने कहा कि पराली की समस्या के लिए किसानों को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।

उन्होंने कहा कि किसानों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह दूसरी फसलों को उगाने के लिए आगे आए जिसमें पराली जैसी समस्या न रहे। साथ

ही किसानों को जागरूक करना होगा कि पराली का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा सके। प्रो. एनवायरमेंट स्ट्डीज डॉक्टर अरूण अहलुवालिया ने कहा कि गांवों को छोटे शहरों में तबदील करने में लगे हैं। जबकि आज जरूरत शहरों से पहाड़ों और गांव की ओर जाने की है। डॉक्टर अरूण ने आगे कहा कि आज किसानों के लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत है। महज बैठक कर चर्चा करने से समस्या का हल नहीं होने वाला। आईआईएचएमआर की डीन एवं प्रो. डॉक्टर अनुराधा एस पलानीचामी ने भी पराली के स्थाई समाधान के बारे में गंभीरता से सोचने और ठोस नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईआरडी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एलसी शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान एनवायरमेंट कान्कलेव आयोजित करने के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए पराली की समस्या से निपटने के संभावित उपायों पर एक प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने कहा कि आईआईआरडी की ओर से किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शुरूआत विशेषज्ञों की चर्चा से की गई है और जल्द ही आईआईआरडी पराली और पर्यावरण से जुड़े अन्य मुद्दों पर बड़े स्तर पर कार्य करने जा रहा है। उन्होने पराली एक समस्या है ये तो सभी कहते हैं लेकिन जरूरत इसका समाधान ढूंढने की है और आईआईआरडी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फ्लायर ग्रुप के सीईओ ने भी इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी। आईआईआरडी निदेशक सुषमा शर्मा ने कहा कि पर्यावरण की देखरेख करना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके कार्यों से पर्यावरण को इतना नुकसान न पहुंचे जिसकी भरपाई करनी मुश्किल हो जाए।

वहीं पंजाब सरकार के क्रॉप रेजेड्यू मैनेजमेंट कृषि विभाग के नोडल अधिकारी मनमोहन कालिया ने सरकार की उन योजनाओं की जानकारी दी जो खास तौर पर पराली की समस्या से जूझ रहे किसानों की समस्या का हल निकालने के लिए चलाई जा रही है। इस दौरान किसान क्लब पंचकूला के जिला प्रधान रामगोपाल, किसान सभा कुरूक्षेत्र के जिला प्रधान गुरूदयाल सिंह ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम के अंत में फ्लायर ग्रुप के सीईओ आनन्द नायर ने सभी अतिथियों को धन्यवाद किया और कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। पराली के मुद्दे पर विशेष चर्चा और इस समस्या का निवारण करने के लिए समाधान जुटाने के लिए विशेषज्ञों की राय के साथ ही कार्यक्रम के दौरान पराली समस्या का समाधान ढूंढने को लेकर कार्य करने वाली संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया।

IIRD HONING YOUTH SKILLS

Since its inception in 2004, IIRD is working to upgrade the skills of rural and urban youths, and providing wage along with the self-employment opportunities. The incorporation of NSDC and other institutional level arrangements in Indian skill development sector has changed the definition of Skill Training in India.

Keeping in pace with the current and future requirements, IIRD has entered into a partnership with National Skill Development Corporation (NSDC) for training 6,000 youths in the next three years.

Further, we are registered as a Project Implementing Agency with the Ministry of Rural Development (MoRD) for training rural youth under Deen Dayal Grameen Kaushalya Vikas Yojna (DDU-GKY), having centres in Uttar Pradesh, Uttrakhand and very soon to be opened in Himachal and Haryana.

IIRD is empanelled with the State Mission Directorates under PMKVY and state-sponsored schemes i.e PMKVY and UPSDM, having its operational centres in Himachal and Uttar Pradesh.

IIRD is also entering into NSDC-CSR Partnership Trainings, we have been given the mandate to train youth from SJVN-affected areas in Shimla, Kullu and Chamba districts.

"IIRD has had a long and successful journey in Skill Development and the same will continue till India becomes the world's number one Skill Capital."

Being the organisation in social sector IIRD is empowering rural youth of the nation through its various Skill Development Programmes. IIRD has trained almost more than one lakh of beneficiaries till now.

Ministry of Rural Development (MoRD) Government of India, in association with State Governments of Uttar Pradesh and Uttrakhand has allotted IIRD to train 680

unemployed rural youth with assured employment. Adding to the initiative IIRD is implementing DDUGKY in the State of Uttar Pradesh and Uttrakhand with training targets of 380 and 300 respectively. The training for almost 300 candidates has been completed in the trades of Zardiosi work and the around 50 students have been placed in various industries In Punjab Haryana, Himachal, Delhi and Uttar Pradesh.

We have placements Tie ups with Human Resource companies and Manufacturing units like Vardhman etc.

The IIRD DDUGKY Uttrakhand center is almost under Completion and training will be commenced in the Last week of December. A dedicated team of mobilizers is currently working in three districts i.e Uttarkashi, Tehri Garhwal and Rudraprayag.

The Quality team is working on the center readiness and installing world-class infrastructure at the center. The category wise targets for Uttrakhand are as

Category of Candidates	SC (56%)	ST (9%)	Minority (18%)	Others	Total
No. of Candidates	168	27	54	51	300

Further 33% women and 3% PwD beneficiaries will enrolled from all categories.

Sector and trade Sanctioned

Sector	Trade/ Job role	Perquisite Trades	Assesment Body	Target
BFSI	Goods & Service Tax (GST) Account Assitant (BSC/ Q0910)	1.Mutal Fund Agent (BSC/Q0601) 2.Accounbts Executive (Payroll) (BSC/Q1201)	BFSI SSC	300

IMPROVISING POTENTIAL THROUGH VARIOUS SKILL DEVELOPMENT PROGRAMS

India has gradually evolved as a fast-developing modern economy due to the abundance of qualified, capable, motivated, and flexible human capital. However, there is a need to further develop and empower this human capital to ensure that the country stands tough and tall in global competitiveness. The term "Skill Development" is used to describe a wider array of institutions and activities which influence employment and earnings. When referring to the preparation of youth and adults for employment, the indirect shift in understanding occurs. The discretion begins to shift from talking about education to talking about skills. Attention extends to informal learnings on the job, structured apprenticeship and other enterprise-based training, along with government and non-governmental training programmes, besides technical and vocational education. Skill Development is a much broader concept, more diverse, hence, more difficult to monitor.

Institutional arrangements in Skill Development

National Skill Development Corporation (NSDC):

NSDC, a Public-Private Partnership was set up in 2008 as a Section 25 company under Companies Act 1956 with a shareholding of GOI (49%) and private sector (51%). It is the nodal organisation for all private sector initiatives in the short-term skilling space. Its mandate primarily includes:

- Catalyse the creation of market-based, scalable business by providing funding through a combination of debt, equity and grants
- Implementing skills voucher programmes
- Driving engagement with industry and businesses
- Promote centres of excellence for the training of trainers in coordination with States and Sector Skills Councils (SSCs)
- Initiating and incubating SSCs
- Discharge any other function as may be assigned to it by the Skill Development Ministry

National Skill Development Agency (NSDA)

NSDA was set up as a Society in June 2013. NSDA focuses on two verticals of Quality Assurance and Policy Research in the skills space. It is majorly responsible for the following activities:

- Operationalise and implementation of National Skills Qualification Framework (NSQF)
- Establish and operationalising a QA framework embedded in NSQF to improve consistency of outcomes in the skills landscape, which includes laying down a framework for training, assessment and certification processes and agencies in the country.
- Operationalise National Skills Qualification Committee (NSQC) to meet its objectives
- Design and implement the National Labour Market Information System
- Develop national protocols for registration and accreditation of private training providers.
- Promote use of Skill India Logo on skill certificates by SSCs/Agencies adhering to the QA framework.
- Anchor Prime Minister's Skill Development Fellow Programme

National Skills Research Division (NSRD), under NSDA, is established to serve as the apex division for providing technical and research support to the Mission. This division acts as a think-tank for MSDE and to be the core skill development hub, which will connect the implementation of the Mission with academic research and data. Its four key functions include research, policy advisory/inputs, career support and knowledge exchange networks.

Directorate General of Training

The two verticals of Training and Apprenticeship Training under DGET, MoLE have been shifted to MSDE from April 16, 2015. Its large institutional framework consisting of ITIs, ATIs, RVTIs and other national institutes will act as the tools of execution for Mission activities. Its other functions include:

- Setting up framework for the structure of courses, assessment, curricula creation, affiliation and accreditation of institutes, under NCVT
- Develop national standards on syllabi, equipment, the scale of space, duration of courses and methods of training
- Advise on training policy in its network of training institutes
- Coordinate functioning of Industrial Training Institutes (ITIs)
- Run training programmes for the training of trainers/instructors.
- Run special institutes for training of women
- Leverage field infrastructure for strong industry interface in all facets of training, including on the job training
- Provide technical support to vocational education across the country
- Anchor and operationalise Apprentices Act, 1961, as overhauled by comprehensive amendments in December 2014
- Operationalise various training schemes through ITIs and Vocational Training Providers (VTPs)

Sector Skill Councils (SSCs):

In order to ensure that the skill development efforts being made by all stakeholders in the system are in accordance with the actual needs of industry, SSCs are being set up. SSCs are industry-led and industry-governed bodies, which will help link the requirements of industry with appropriately trained manpower. SSCs are discharging the following functions:

- Identification of skill development needs including preparing a catalogue of types of skills, range and depth of skills to facilitate individuals to choose from them.
- Development of a sector skill development plan and maintain skill inventory.
- Determining skills/competency standards and qualifications and getting them notified as per NSQF.
- Standardisation of affiliation, accreditation, examination and certification process in accordance with NSQF as determined by NSQC. May also conducts skill-based assessment and certification for QP /NOS aligned training Programmes.
- Participation in the setting up of affiliation, accreditation, examination and certification norms for their respective sectors.
- Plan and facilitate the execution of Training of Trainers along with NSDC and States.
- Promotion of academies of excellence.
- Lays special emphasis on the skilling needs of ST/SC, differently-abled and minority population
- SSCs ensures that the persons trained and skilled in accordance with the norms laid down by them are assured of employment at decent wages.

Schemes for Skill Development in India

- Ministry-wise Skill Development Schemes
- Financial Assistance for Skill Training of Persons with Disabilities
- Skill development for Minorities
- Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana
- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
- Pradhan Mantri Kaushal Kendra
- National Apprenticeship Promotion Scheme
- Craftsmen Training Scheme
- Apprenticeship Training
- Scheme for Higher Education Youth in Apprenticeship and Skills
- Green Skill Development Programme
- National Qualifications Register, with many other vital programmes

Harinder Verma, Project Manager

एड्स के विरुद्ध सैकड़ों छात्रों ने नगर में निकाली जागरुकता रैली

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व एडस दिवस के मद्देनजर ठियोग के छात्र जमा दो स्कूल के सैकड़ों छात्रों ने ठियोग नगर में जागरुकता रैली का आयोजन किया। स्कूल की एनएसएस इकाई के नेतृत्व में सुभाष चौक से सब्जी मंडी तक छात्रों ने एड्स जैसी लाईलाज बीमारी से बचने व इसके प्रति जागरूक रहकर सभी बचाव के उपाय करने की अपील लोगों से की।

रैली में एनसीसी, नेचर क्लब सहित सभी अध्यापकों ने भी हिस्सा लिया। स्कूल के एनएसएस प्रभारी रमेश डोगरा ने रैली का संचालन किया। इससे पूर्व स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को एड्स रोग व उससे बचाव के बारे में जानकारी दी गई। उसके बाद हाथों में बैनर पोस्टर लेकर छात्रों ने नगर में लोगों का नारों के जारिए भी जागरूक किया।

लावारिस कुत्ता गोद लेने पर पार्किंग व कूड़े की फीस माफ

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नगर निगम शिमला द्वारा लावारिस कुत्तों के आतंक से निपटने के लिए बनाई गई नीति को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत लावारिस कुत्ते को गोद लेने पर नगर निगम की एक पार्किंग स्लॉट और कूड़े की फीस माफ होगी। नगर निगम के सदन ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। लावारिस कुत्तों की देखभाल में भी प्रशासन मदद करेगा। निगम की इस पहल को सफलता भी मिली है। लावारिस कुत्तों को पालने के लिए प्रशासन के पास अब तक 33 आवेदन पहुंच चुके हैं। शिमला शहर में 2000 से ज्यादा लावारिस कुत्ते हैं। अगर यह पहल सफल हो गई तो शिमला शहर में लावारिस कुत्तों की समस्या खत्म हो जाएगी।

नगर निगम शिमला के आयुक्त पंकज राय कुछ समय पहले एक प्रशिक्षण के सिलसिले में अमेरिका के दौरे पर गए थे। उन्होंने बताया कि वह जिस शहर में रह रहे थे, वहां लावारिस कुत्ते दिखाई नहीं दिए तो उन्हें जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस संबंध में पड़ताल की तो उन्हें यह लगा कि यह काम शिमला में भी किया जा सकता है।

DYFI ने किया धरना प्रदर्शन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

dyfi ने प्रदेश में पटवारी परीक्षा में हुई गड़बड़ी व प्रदेश के युवाओं के साथ हो रहे खिलवाड़ और पीजीटी भर्ती मामले में बाहरी राज्यों को खुली छूट के खिलाफ शिमला ज़िला मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने में अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष बलबीर पराशर, सचिव चन्दर कांत वर्मा, अध्यक्ष पवन शर्मा, अनिल नेगी, कपिल शर्मा, शौर्य, अनिल, हैप्पी, गौरव, कविता, अंजलि सहित अनेक लोगों ने भाग लिया।

dyfi का मानना है कि एक तरफ सरकार द्वारा नवउदारवादी नीतियां देश मे थोपी जा रही है दूसरी तरफ सिर्फ जुमले पेश कर युवाओं को ठगा जा रहा है कभी 2 करोड़ नौकरी के नाम पर और कभी देश ख़तरे में है जैसे जुमले दिखा कर और अगर युवा अपनी मांगे उठाने सड़कों पे आता है तो उस पर पुलिस दमन कर देश द्रोही होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। dyfi का मानना है जब से प्रदेश में जयराम सरकार आयी है तब से सिर्फ जुमले ही दिखाए जा रहे है मुख्यमंत्री हो या मंत्री सब नाच गाने में या जूठे भाषणों में ही खुश है जनता चाहे जिये या मारे सरकार को कोई फर्क नई पड़ता है इस लिए कलपि ने पटवारी परीक्षा में हुए घफले को सीधे तौर पर सरकार द्वारा किया गया घोटाला कहा है जिस में 7 से 10 करोड़ का घपला सरकार ने किया है और नोजवानो को ठोकरे खाने पर मजबूर किया है।

dyfi ने सरकार को चेतावनी दी है कि पटवारी परीक्षा की न्यायिक जांच हो, परीक्षा फिर से कराई जाए और किसी भी युवा से कोई फीस न ली जाए व बिजली बोर्ड में निकली भर्तियों की अभी से सही तैयारी हो व रइज के 296 पदों में बाहरी राज्य की भर्ती न हो और रइज की परीक्षा के फार्म भरने की तिथि 22 नवंबर से बढ़ा कर 5 दिसम्बर तक कि जाए ताकि युवा ठोकरे न खाऐं। द रीव टाइम्स से बात कर अध्यक्ष पवन शर्मा और सचिव चन्द्र कांत वर्मा ने यह जानकारी दी।

100 नई इलेक्ट्रिक बसें और आएंगी, शिमला समेत सात शहरों को भी मिलेंगी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अब तीसरे चरण में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें और आएंगी। ऐसे में शिमला समेत सात शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। शिमला के अलावा अन्य शहर भी अब पर्यावरण फ्रेंडली इन बसों में यात्रा करने का लाभ ले सकेंगे। शिमला में पहले से ही 50 इलेक्ट्रिक बसें चली हुई है। इस बार जो क्लस्टर एचआरटीसी की ओर से बनाया गया है, उसमें फिर से हिल्स क्वीन को शामिल किया गया है। ताकि, शिमला को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा सकें। एचआरटीसी प्रबंधन 15 दिसंबर तक केंद्र सरकार को पूरा प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। इसमें चार्जिंग प्वाइंट बनाने से लेकर, बसों को चलाने का पूरा प्लान होगा। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक बसें शिमला और मनाली से रोहतांग के लिए चलाई जा रही हैं। मनाली में ये बसें 25 सीटर हैं। शिमला में जो बसें चल रही है, वे 30 सीटर हैं। अब यहां 20 सीटर बसें भी चलाई जा रही है। मनाली से रोहतांग के लिए चलने वाली बसें चार्ज होने पर छह घंटें तक का समय लगाती हैं और 200 किमी चलती हैं। शिमला में इलेक्ट्रिक बसें आधे घंटे में फुल चार्ज होती है और 200 किलोमीटर का सफर तय करती है।

नगर निगम भारी बिलों से कर रही आमजन का शोषण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

शिमला नागरिक सभा ने कूड़े, पानी व सीवरेज के भारी बिलों के खिलाफ नगर निगम शिमला के आयुक्त के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नागरिक सभा ने बिलों में संशोधन को लेकर आयुक्त को पन्द्रह दिन का समय दिया है। अगर इस दौरान उपभोक्ताओं को सही बिल जारी न किये गए तो नागरिक सभा आयुक्त का घेराव करने से भी नहीं चूकेगी। प्रदर्शन में अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, सचिव कपिल शर्मा, उपाध्यक्ष राजीव ठाकुर टुन्नु, डॉ. राजेन्द्र चौहान, किशोरी ढटवालिया, बाबू राम, चन्द्रकान्त वर्मा,रमन थारटा, रामप्रकाश रामू, दलीप कुमार, मुनीश तलवार, राजकुमार, नरेंद्र, लायक राम, इंद्रजीत, किरपा राम, आर सी वर्मा, बाबू राम शर्मा, अमित, नीरज, अरुण, संजीव, सरोज शर्मा, रितु लुम्बा, अनिता, सुनीता, आदि शामिल रहे। नागरिक सभा का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त आयुक्त से मिला व एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, सचिव कपिल शर्मा व उपाध्यक्ष राजीव ठाकुर टुन्नु ने डीसी ऑफिस पर हुए प्रदर्शन को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला पानी, कूड़ा व सीवरेज जैसे बुनियादी सुविधाओं को ठेका अथवा निजी हाथों में सौंपने की कवायद में जुटा हुआ है जिसे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने घोर निराशा व्यक्त की है कि नगर निगम शिमला शहर के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 से 50 हजार के कूड़े के बिल जारी कर रहा है। लगभग इतनी ही राशि के पानी के बिल जारी किए जा रहे हैं। इस तरह हजारों रुपये का आर्थिक बोझ घरेलू उपभोक्ताओं पर लादा जा रहा है। ये बिल हर महीने जारी न करके छः महीने बाद जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को हजारों रुपये के ग़लत बिल देने के लिए

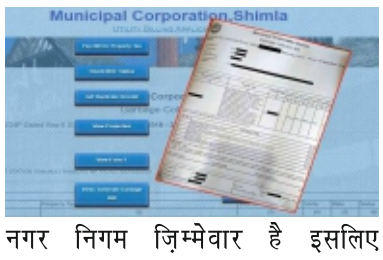

नगर निगम ज़िम्मेवार है इसलिए उपभोक्ताओं के हर रोज नगर निगम कार्यालय के चक्कर कटवाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिकारियों को समयबद्ध रूप से अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम के साथ न केवल वार्डों का दौरा करना चाहिए बल्कि वार्ड में सुविधा केन्द्र के रूप में भी अपनी सेवाएं मुहैया करवानी चाहिए। उन्होंने नगर निगम से यह भी मांग की है कि कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से पहले शहर की सामाजिक संस्थाओं व नागरिकों से सुझाव अवश्य लेने चाहिए।

कोटखाई प्रकरण में कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी सरकार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कोटखाई में छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म एवं हत्या मामले में राज्य सरकार कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह के मौके पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केस के कानूनी पहलुओं पर गौर किया जाएगा।

मामला अब अंतिम चरण में है। जांच के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंची है। केस कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में जो भी चीजें होंगी, वह कानून के दायरे में ही रहकर होंगी। ऐसी परिस्थितियों में इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं है।

पीड़ित परिवार ने मांगा है इंसाफ

दुष्कर्म एवं हत्या प्रकरण में मृतका के माता-पिता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिलकर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई थी। छात्रा की मां ने कहा था कि उनकी बेटी को अकेला आरोपित नीलू नहीं मार सकता था शव को ठिकाने लगाने में वह शामिल रहा होगा, लेकिन शक है कि वारदात को तीन से चार लोगों से अंजाम दिया। वहीं पिता ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमत्री के फेसबुक अकाउंट से संदिग्धों के पहले फोटो वायरल हुए और फिर डिलीट कर दिए गए। पूरे मामले में अधूरा सच ही सामने लाया है। गुड़िया न्याय मंच ने 4 जुलाई 2017 को तांदी जंगल में हुई गुड़िया की हत्या व बलात्कार के मामले में सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ में फोरेंसिक विभाग के दो सहायक निदेशकों के बयानों का संज्ञान लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुड़िया मामले की पुनः जांच की मांग की है। मंच ने प्रदेश सरकार को आगाह किया है कि वह गुड़िया को न्याय देने के लिए तुरन्त उचित कदम उठाए अन्यथा गुड़िया न्याय मंच दोबारा से इस मुद्दे पर सड़कों पर उतर आएगा।

गौरतलब है कि भाजपा ने चुनाव के वक्त गुड़िया मामले को प्रमुख मुद्दा बनाया था अतः अब वक्त आ गया है कि वह अपने वायदे को पूर्ण करें व इस मामले की तह तक जाने के लिए न्यायिक जांच गठित करें। सीबीआई कोर्ट में चल रही कार्रवाई से एक के बाद एक कड़ियाँ खुल रही हैं।

गुड़िया न्याय मंच शुरू से इस बात को कहता रहा है कि गुड़िया का बलात्कार व निर्मम हत्या किसी एक दरिंदे का कार्य नहीं था बल्कि यह एक सामूहिक सुनियोजित जघन्य अपराध था। इस अपराध में शामिल असली अपराधियों को राजनेताओं, नौकरशाहों व प्रभावशाली व्यक्तियों का आश्रय रहा है। फोरेंसिक विभाग की जांच ने इस बात को पुख्ता कर दिया है कि गुड़िया का बलात्कार व निर्मम हत्या कोई साधारण मामला नहीं था बल्कि यह सुनियोजित षड़यंत्र था।

आइजीएमसी में पहली बार हुई बैरियेट्रिक सर्जरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में लोगों को मोटापे से आधुनिक तकनीक से निजात दिलाने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आइजीएमसी) शिमला में शुरुआत हो चुकी है। आइजीएमसी शनिवार को ऐसी ही सर्जरी का गवाह बना। अस्पताल में मोटापे से पीड़ित एक व्यक्ति से फालतू चर्बी निकालने के लिए बैरियेट्रिक सर्जरी की गई। आइजीएमसी में इस प्रकार की पहली सर्जरी हुई।

सोलन जिले के अर्की निवासी व्यक्ति की सर्जरी ढाई घंटे चली। इस व्यक्ति का वजन 107 किलो था। डॉक्टरों की टीम ने लेप्रोस्कोपी से यह ऑपरेशन किया। मोटापे को कम करने के लिए की गई सर्जरी में अमाशय से कुछ हिस्से को काटकर छोटा किया गया। ऐसा करने पर व्यक्ति चाहकर भी ज्यादा भोजन नहीं कर पाएगा और अगर कर भी लेगा तो उल्टी कर देगा।

आइजीएमसी में बैरियेट्रिक सर्जरी के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे। उन्होंने अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर लगी मशीन में ऑपरेशन थियेटर में हो रही सर्जरी का लाइव प्रसारण एक घंटा 15 मिनट तक देखा। ऑडिटोरियम में एमबीबीएस और नर्सिंग व पैरामेडिकल के विद्यार्थियों को लाइव सर्जरी सीखने का मौका मिला।

बैरियेट्रिक सर्जरी से ब्लडप्रेशर, डायबिटीज, हृदय व घुटने से संबंधित बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। रोबोटिक सर्जरी का प्रदर्शन आइजीएमसी में रोबोट से सर्जरी करने का तरीका भी कार्यशाला में पहुंचे डॉक्टरों ने स्क्रीन पर दर्शाया। इसमें दिखाया गया कि रोबोटिक सर्जरी क्या है, कैसे एक रोबोट सर्जरी करता है जहां पीछे बैठे डॉक्टर रोबोट को मैनुअली हैंडल कर रहे होते हैं। हर्निया के चार मरीजों की सर्जरी आइजीएमसी में शनिवार को हर्निया के चार मरीजों की भी सर्जरी हुइ। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हर्निया से पीड़ित इन चार मरीजों को भी अन्य राज्यों के डॉक्टरों ने ऑपरेट किया।

शिमला में कूड़ा फेंका तो मौके पर वसूला जाएगा 500 रुपये जुर्माना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राजधानी शिमला को साफ-सुथरा बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रैंकिग हासिल करने के लिए नगर निगम ने सख्त फैसले लिए हैं। निगम के हाउस में निगम आयुक्त पंकज राय ने बताया कि शहर में खुले में कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा।

मौके पर कूड़ा फेंकने वाला यदि जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं कर सका तो बाद में जुर्माने की राशि दोगुनी वसूली जाएगी। शहर को साफ बनाने के लिए प्रशासन ने इस बार सख्त नियम लागू करने का फैसला लिया है। इससे पहले निगम की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन लोगों ने खुले में कूड़ा फेंकना नहीं छोड़ा।

शहर में डोर-टू-डोर गारबेज योजना शुरू होने के बावजूद कूड़े के डंपर भरे रहते थे। आम लोग भी डंपरों के आसपास कूड़ा बिखेरते थे। इससे निगम की मेहनत पर पानी फिर जाता था। इस बार निगम प्रशासन ने पूरे शहर से डंपर उठवा दिए हैं। इसके बाद फैसला लिया कि खुले में कूड़ा फेंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। गारबेज की ऑनलाइन पेमेंट को रिव्यू करने की मांग शहर के पार्षदों ने गारबेज का बिल ऑनलाइन करने के फैसले को रिव्यू करने की मांग की। पार्षद शैलेंद चौहान ने कहा कि इससे आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है।

हर शहरी के पास ऑनलाइन बिल देखने की सुविधा नहीं है। ऐसे में आम लोगों को इससे राहत देने के लिए निगम प्रशासन को इसे रिव्यू कर लेना चाहिए।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

विद्यार्थी की हर गतिविधि की जानकारी रेडियो पर सुनते हैं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

सिरमौर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मोगीनंद के छात्रों ने स्कूल के जीव विज्ञान प्रवक्ता डॉ. संजीव अत्री की अगुवाई में अपना रेडियो चैनल ऐप शुरू किया है। ऐप के जरिये स्कूल अपने सारे कार्यक्रम और गतिविधियों को रेडियो पर जारी करता है। इस ऐप को हेलो मोगीनंद का नाम दिया गया है।

इस ऐप को 11वीं कक्षा की मेडिकल की छात्रा सलोनी ऑपरेट करती हैं। ऐप के जरिये अभी तक स्कूल के अनेक कार्यक्रमों को 7 देशों में रेडियो के माध्यम से सुनाया जा चुका है। डॉ. संजीव अत्री ने बताया कि उन्होंने विज्ञान विषय के छात्रों के साथ मिल कर रेडियो ऐप डिजाइन किया। ऐप स्कूल के नाम से चलाया जा रहा है। ऐप को चलाने के लिए स्कूल में 14 बच्चों की टीम कार्य करती है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों तक हर गतिविधि को रिकॉर्ड करने के बाद इसे ऐप के माध्यम से सुनाया जाता है।

नाहन के मोगीनंद स्कूल में प्रवक्ता के पद पर तैनात डॉ. अत्री ने राजस्थान से जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है। इस ऐप के लिए उन्होंने अंडे की ट्रे से पूरे स्टूडियो को तैयार किया है।

स्टूडियो को बनाने पर मात्र 600 रुपये खर्च किए हैं। अभी तक ऐप पर रिकॉर्ड प्रोग्राम ही चलाए जाते हैं, 14 फरवरी 2020 के बाद इसे लाइव कर दिया जाएगा। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। ऐप को स्कूल प्रवक्ता और बच्चों ने मिलकर डिजाइन किया है।

जनमंच में गैरहाजिर अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

भोजनगर में आयोजित जनमंच कार्य क्रम से गैर हाजिर अधिकारियों को नोटिस जारी कर मंत्री डॉ. सैजल ने जवाब मांगने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जोगेंद्रा सहकारी बैंक के कुछ अधिकारी कार्यक्रम में नहीं आए थे। इस कारण संबंधित शिकायतों का निपटारा भी नहीं हो सका। उक्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्यक्रम में भाग नहीं लेने पर कारण बताओ नोटिस देने के लिए उपायुक्त सोलन को निर्देश दिए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उक्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित जनमंच कार्यक्रम में अधिकारियों के न आने से आम लोगों को होने वाली परेशानी सहन

नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं ऐसे सभी मामलों की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाई जाएगी। उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि जनमंच के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी उपमंडलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उनसे कहा गया है कि वे जनमंच में प्राप्त शिकायतों और उनके निवारण के संबंध में शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित करें।

नगर परिषद ने हटाया अतिक्रमण, 15 कारोबारियों का सामान जब्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

नगर परिषद की टीम ने मुख्य बाजार सहित अन्य स्थानों पर सड़क पर अतिक्रमण करके बैठे कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 15 दुकानों का सामान जब्त किया। नगर परिषद की गाड़ी बाजार में पहुंचते ही कारोबारियों में हड़कंप मच गया और कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कारोबारियों ने सामान उठाने का कार्य शुरू कर दिया। नगर परिषद की टीम ने मुख्य बाजार से पुरानी कचहरी और लक्कड़ बाजार से ठोडो ग्राउंड के पास कब्जा कर बैठे कारोबारियों के सामान को जब्त कर गाड़ी में भर लिया। कुछ कारोबारी टीम के आगे गिड़गिड़ाने लगे। कुछ जगह पर कारोबारियों और नगर परिषद कर्मचारियों के बीच कहासुनी भी हुई। कुछ कारोबारियों को सामान को समेटने का मौका तक नहीं मिला। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी नगर परिषद की ओर से कारोबारियों को सड़क पर अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन हर बार कारोबारी नगर परिषद की कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए अपना सामान सड़क पर सजा देते हैं। जोकि बाजार में गुजरने वाले लोगों के लिए परेशानी बनता है। नगर परिषद के सेनिटेरी इंस्पेक्टर ने बताया कि मुख्य बाजार, लक्कड़ बाजार और ठोडो ग्राउंड के पास अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की गई। 15 कारोबारियों के सामन को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमों को दरकिनार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद गंभीर है।

यातायात नियंत्रित करने खुद सड़क पर उतरे एसपी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

एसपी दिवाकर शर्मा ने टीम के साथ को नए बस अड्डे के पास यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। शहर में एसपी ने स्वयं दुकानों पर जाकर कारोबारियों से यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सहयोग की अपील की।

दिलचस्प यह रहा कि कई जगह एसपी कारोबारियों के आगे हाथ जोड़ कर अपील करते दिखे। इस दौरान एसपी ने एएसपी विनोद धीमान, डीएसपी अशोक वर्मा सहित अन्य पुलिस कर्मियों की टीम के साथ सड़क के किनारों पर अतिक्रमण करने वाले कारोबारियों से अतिक्रमण को हटाने की अपील की। एसपी ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

गौरतलब है कि आईएसबीटी ऊना के शुरू होने से शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू

करने के लिए काफी मुश्किलें पेश आ रही थीं। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। बाजार में कारोबारियों से यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने की अपील करते हुए एसपी को देख हर कोई हैरान हो गया। एसपी दिवाकर शर्मा कारोबारियों से दुकानों के आगे सड़क पर रखे सामान को हटाने के लिए अपील की। इसके अलावा एसपी दिवाकर शर्मा ने अपील के बावजूद सड़क पर दुकानों के आगे अतिक्रमण करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

मुख्यमंत्री ने 140 करोड़ के विकास कार्यों का किया शुभारंभ

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला ऊना के दो दिवसीय दौरे के दौरान बिते दिनों 140 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। गुरुद्वारा साहिब किला बाबा बेदी साहिब में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन को इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब तक जाने वाली सड़क के सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने इस सड़क के सुधार के लिए 15 लाख रुपये देने की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 11.05 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आईटीआई ऊना के भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने 3.74 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले ईवीएमध्वीवीपैट वेयर हाउस ऊना का शिलान्यास किया। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने कुटलैहड़ निर्वाचन क्षेत्र, ऊना के कुछ भाग और अंब खंड के गांवों के लिए 30 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया। उन्होंने 2.92 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर निर्मित होने वाले स्वास्थ्य विभाग के टाइप-2 और टाइप-3 के 6-6 आवासीय भवन की भी आधारशिला रखी।

उन्होंने 29 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर ऊना के रामपुर स्थित एचआरटीसी वर्कशॉप के समीप सब्जी मंडी भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कुठार खुर्द से कुठार कलां सड़क के सुधार और मोहल्ला ब्राह्मणा सड़क, लोअर भरोलियन, लोअर देलां की संपर्क सड़क को चौड़ा करने और कुठार खुर्द और

कुठार कलां की सर्कुलर सड़क को पूर्ण करने का भूमि पूजन किया। इस पर 3.20 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। उन्होंने 2.91 करोड़ रुपये की लागत से आरटीओ ऊना के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया।

नक्शा पास न करवाया तो न मिलेगी बिजली, न ही पानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

जिले के सरहदी क्षेत्र में मैहतपुर - बसदेहड़ा नगर परिषद के साथ लगती पंचायतों रायपुर सहोड़ां, चढ़तगढ़ तथा जखेड़ा में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने शिकंजा कस दिया है। इसके चलते अब इन पंचायतों के ग्रामीणों को नये घर का निर्माण, बिजली तथा पेयजल आपूर्ति के लिए नए कनेक्शन लेना मुश्किल हो गया है। खास बात यह कि इन गांवों में संपन्न एवं निर्धन परिवारों को भी टीसीपी के नियमों के तहत ही नक्शा पास करवाना जरूरी हो गया है। टीसीपी के सख्त रुख के चलते ही जखेड़ा पंचायत के कई ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन नहीं मिल सका।

बताया जा रहा है उन्होंने टीसीपी के नियमानुसार नक्शा पास नहीं करवाया था। विभाग ने विद्युत एवं आईपीएच विभाग को भी पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि वह किसी भी सूरत में बिना नक्शे के बिना विद्युत एवं पेयजल के नए कनेक्शन जारी न करे। सरकार के कड़े रुख के चलते ग्रामीणों को निकट भविष्य में काफी मुश्किलें पैदा होने वाली है।

जानकारी के मुताबिक नए घर के निर्माण के लिए जितना क्षेत्रफल कवर किया जाएगा, उसके मुताबिक पीसीपी का नक्शा पास होगा। उसके अनुरूप ऑनलाइन फीस जमा करवानी होगी। नक्शा पास करवाने से लेकर अन्य तमाम औपचारिकताएं ऑनलाइन ही पूर्ण करनी होगी।

प्लास्टिक के कचरे से बने बेंच पर अब आराम फरमाएंगे लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में सिरमौर जिला में एक नई पहल की गई है। पर्यावरण में जहर घोल रहे प्लास्टिक कचरे को अब न केवल ठिकाने लगाया जाएगा, बल्कि दैनिक उपयोग के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। सिरमौर में प्लास्टिक के कचरे से बैंच तैयार करने की जिला प्रशासन ने पहल की है। सर्वप्रथम उपायुक्त कार्यालय के बाहर आम लोगों के लिए बैंच तैयार किए जाएंगे। प्लास्टिक की बोतलों में बंद प्लास्टिक के लिफाफे, रैपर आदि से आरामदायक बेंच तैयार किए जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जिला सिरमौर हमेशा आगे रहा है। गणतंत्र दिवस पर स्मृति चिन्ह के स्थान पर एक - एक पौधा उपहार के रूप में देकर जिला प्रशासन ने दो साल पहले एक पहल शुरू की थी। अब सिरमौर जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान छेड़ा गया है। श्री रेणुका जी में अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले के समापन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अभियान का आगाज किया था। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, पानी आदि की प्लास्टिक की बोतलों में प्लास्टिक के लिफाफे, टॉफियों के रैपर, चिप्स के खाली पैकेट आदि भरे गए हैं।

रेहड़ी-फड़ी धारकों को बसाने के लिए जल्द बनेगी डीपीआर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

औद्योगिक नगरी परवाणू में रेहड़ी-फड़ी धारकों को स्थायी तौर पर बसाने के लिए नगर परिषद परवाणू इससे संबंधित डीपीआर बनाकर शहरी निदेशालय को भेजेंगी। हिमुडा की ओर से चिन्हित जगह पर वेंडिंग जोन बनाने के लिए नगर परिषद परवाणू के पास साधनों की कमी है। जिसके चलते नप को शहरी निदेशालय की ओर ताकना पड़ रहा है। शहरी निदेशालय से इसके लिए फंड मंजूर हो जाने के बाद परवाणू में स्टेबल वेंडर मार्किट बनाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। नगर परिषद परवाणू के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद परवाणू के कार्यकारी अधिकारी सुधीर शर्मा ने की। गौरतलब है की परवाणू में स्थाई तौर पर वेंडिंग जोन बनाने का काम काफी अरसे से लंबित है। यहां हाईकोर्ट के आदेशों के चलते सेक्टर एक में चल रहे रेहड़ी खोखे हटाए जाने है, लेकिन उस से पहले रेहड़ी खोखा चलाकर अपनी आजीविका कमा रहे लोगों को स्थाई तौर पर बसाया जाना है। हिमुडा ने इसके लिए नगर में कुछ स्पॉट्स चिन्हित करके नगर परिषद को सौंपे है, लेकिन इन चिन्हित स्पॉट्स पर वेंडर्स बसाने के लिए उस पर पहले काफी खर्चा करना पड़ेगा, जबकि नगर परिषद के पास फिलहाल उतने साधन नहीं है। इसी के चलते बैठक में इस से सम्बंधित डीपीआर बनाकर शहरी निदेशालय भेजने का निर्णय लिया गया।

सिरमौर में प्रत्येक परिवार को मिलेगा कपड़े का मुफ्त थैला

द रीव टाइम्स, सिरमौर

पॉलिथीन मुक्त सिरमौर योजना के तहत शिलाई विकास खंड कार्यालय परिसर में शिविर लगाया गया।

इसकी अध्यक्षता जिलाधीश डॉ. आरके परुथी ने की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्लास्टिक, पॉलिथीन का प्रयोग जल, पर्यावरण और मानव सेहत के लिए हानिकारक है। पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक व पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा रही है। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पॉलिथीन मुक्त सिरमौर योजना की व्यापक पहल की गई है। उन्होंने

बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जिला के प्रत्येक परिवार को एक कपड़े का थैला निःशुल्क दिया जाएगा।

सिरमौर जिला के छह विकास खंडों के 1182 स्वयं सहायता समूह व 1283 महिला मंडलों को जोड़ा जाएगा। आवश्यक प्रशिक्षण व तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला में 164 शिलाई अध्यापिकाएं कार्यरत हैं।

शिलाई अध्यापिकाएं थैले तैयार करने के लिए दो-दो महिलाओं का प्रशिक्षण के लिए चयन करेंगी। प्रथम चरण में महिलाओं को थैला बनाने के बदले में उनके श्रम के अनुसार उतने मूल्य का कपड़ा निशुल्क दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को थैले उपलब्ध करवाने के बाद बाजार से सामान खरीदते समय यदि प्लास्टिक के थैले प्रयोग किए जाते हैं तो ग्राम पंचायत ऐसे लोगों को दंडित भी कर सकती है। थैलों के लिए कपड़े का प्रबंध माता बाला सुंदरी त्रिलोकपुर से किया जा रहा है।

ढाई करोड़ रुपये से चकाचक होगी नाहन की सड़कें

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

नाहन में सड़कों की कायाकल्प होने वाली है। शहर की सड़कों पर लोक निर्माण विभाग और नगर परिषद इंटरलॉक टाइलें लगाने जा रहा है। इस पर करीब ढाई करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग के अधीन गुन्नूघाट से रानीताल तक की सड़क पर इंटर लॉक टाइलें लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इस पर लगभग 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा शहर की अन्य कई सड़कों में अब तारकोल की जगह इंटरलॉक टाइलें लगेंगी। नगर परिषद शीघ्र इसके टेंडर करवाने जा रही है।

इन पर करीब दो करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। नाहन शहर में सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। कई सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे पड़ गए हैं। जबकि पैदल चलने वाले रास्तें भी खराब हो गए हैं। अब इनको सुधारने के लिए नगर परिषद करीब दो करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है। नगर परिषद ने सड़कों पर इंटरलॉक टाइलें लगाने के लिए लगभग दो करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। जल्द ही इन सड़कों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

नहीं रहे कैंसर का इलाज करने वाले विश्व विख्यात डॉक्टर यशी ढोंडेन

द रीव टाइम्स, कांगड़ा

तिब्बतियन पद्धति से कैंसर का इलाज करने वाले पद्मश्री डॉ. येशी ढोंडेन की बीते दिनों मैक्लोडगंज स्थित उनके आवास अशोका होटल में मौत हो गई। तिब्बतियन डॉक्टर ढोंडेन बौद्ध धर्मगुरु दलाईलामा के निजी चिकित्सक भी रह चुके है। उनकी मौत से जहां तिब्बती समुदाय गम में डूबा है, वहीं जिन कैंसर के मरीजों को उन्होंने नई जिंदगी दी, उनकी आंखें भी नम हैं। डॉ. येशी की मृत्यु की खबर सुनते ही सुबह उनके निवास स्थान के बाहर सैकड़ों तिब्बती और स्थानीय लोग जमा हो गए। डॉ. ढोंडेन के पारिवारिक सदस्य लोबसांग त्सेरिंग ने बताया कि उनका संस्कार मैक्लोडगंज में किया जाएगा। दो दिन तक उनकी देह की तिब्बतियन पद्धति के अनुसार पूजा होगी। डॉ. येशी कैंसर के अलावा ट्यूमर, एड्स, सुराइसिस, हेपेटाइटिस ल्यूकेमिया आदि गंभीर रोगों का भी इलाज करते थे। तिब्बती चिकित्सा पद्धति में बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें 20 मार्च, 2018 को पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था। निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री डॉ. लोबसंग सांग्ये ने डॉ. येशी ढोंडेन के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। तिब्बती चिकित्सा एवं ज्योतिष संस्थान 'मेन ट्सी खंग' धर्मशाला के महासचिव त्सेरिंग फुंत्सोक ने बताया कि तिब्बती चिकित्सा पद्धति को दुनिया भर में प्रचारित करने वाले बहुत बड़ा नाम चला गया। डॉ. येशी के शिष्य रहे डॉ. केलसंग ढोंडेन, डॉ. नामग्याल कुसर, डॉ. पसांग ग्याल्मो खंगकर ने कहा कि गुरुजी ने अपना पूरा जीवन समाजसेवा में लगा दिया।

सुस्त ब्लाकों पर डीसी सख़्त, वापस मांगा पैसा

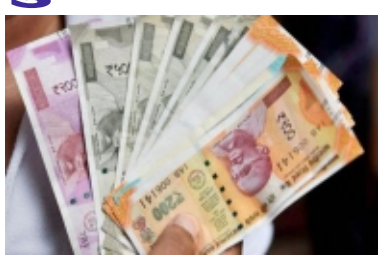

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

उपायुक्त ने विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2017 से पहले विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि जो खर्च नहीं हुई, उसे वापस कर दें। इसका उपयोग अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सके। डीसी राकेश कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में कांगड़ा जिला के विकास खंडों में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर डीआरडीए के सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला के सभी खंड विकास अधिकारियों, डीआरडीए, पंचायती राज के अधिकारियों ने भाग लिया। उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा के तहत जिले में दीर्घकालिक विकास के लिए काम किया जा रहा है। कांगड़ा जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के अंतर्गत 69 करोड़ 73 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। अब तक 23 लाख 86 हजार 594 कार्यदिवस अर्जित कर जिले में योजना का 45 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 585 स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 1754 स्वयं सहायता समूहों को 13.25 करोड़ की सहायता दी गई है। पंचायत स्तर पर ठोस कूड़ा कचरा निष्पादन के लिए भी उचित कार्ययोजना तैयार करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने विकास खंड अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना जरूरी है।

कांगड़ा की पंचायतों में बनेंगे 150 खेल मैदान

द रीव टाइम्स, कांगड़ा

नशे की गिरफ्त में आ रही कांगड़ा जिला की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने नई पहल की है।

जिले की पंचायतों में चार माह के भीतर वहलीबाल, हैंडबाल और खो-खो के 150 मैदान बनाए जाएंगे। मकसद, युवा खेल गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा भाग ले सकें। डीसी ने चार माह के भीतर 150 खेल मैदान बनाने के लिए सभी बीडीओ को निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति चिंता का विषय है। पंचायतों में खेल मैदान बनाने पर सरकार का ज्यादा खर्चा नहीं आएगा।

इसलिए, हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि चार माह के भीतर पंचायतों में 150 खेल मैदान बना दिए जाएंगे। यह मैदान खासकर वॉलीबाल, हैंडबाल और खो-खो के लिए होंगे। अगर पंचायत स्तर पर खेल मैदान होंगे तो युवाओं का ध्यान खेल गतिविधियों में जाएगा। युवाओं के पास जब भी अतिरिक्त समय होगा तो वह खेलेंगे।

प्रजापति ने कहा कि दिसंबर तक नूरपुर, इंदौरा और फतेहपुर में खेल मैदान तैयार हो जाएंगे। क्योंकि, इन इलाकों के ज्यादा युवा

नशे की गिरफ्त में हैं। इसलिए सबसे पहले वह इन इलाकों को फोकस करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि पंचायत के हर वार्ड में खेल मैदान बनाया जाएगा ताकि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जा सके।

तालाब में स्नान करने उतरी बेटी की डूबने से मौत, मां की भी गई जान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

हिमाचल के कांगड़ा जिले में नूरपुर की हटली-जम्बाला पंचायत के प्रसिद्ध मुर्दाली मंदिर के नजदीक तालाब में मां-बेटी की डूबने से मौत हो गई। सुनीता देवी (56) पत्नी किशन चंद निवासी दाड़ी (धर्मशाला) और बेटी सीमा देवी (23) पत्नी अमित शर्मा निवासी नालटी भट्टू (पालमपुर) की रहने वाली थीं।

पुलिस के अनुसार सुनीता अपनी बेटी सीमा को मुर्दाली में बने तालाब में स्नान करवाने आई थी। सुनीता का बेटा सुरेश भी साथ आया था। मंदिर के नजदीक ऊंचाई से गिरते

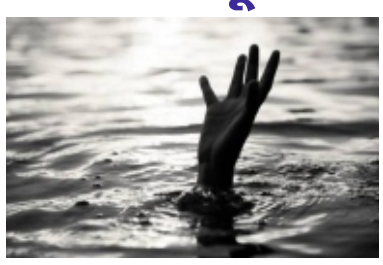

पानी से गहरा तालाब बना हुआ है। मान्यता है कि जो स्त्री उस झरने में स्नान करती है, मां की कृपा से उसे संतान प्राप्ति होती है। इसी के चलते सुनीता देवी अपनी बेटी को लेकर यहां आई थी। जैसे ही बेटी तालाब में स्नान करने उतरी तो वह गहरे पानी में डूबने लगी। पास ही खड़ी मां ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों गहरे पानी में समा गईं।

बेटे सुरेश ने उनके चिल्लाने की आवाजें सुनी लेकिन तैरना नहीं आने के चलते वह कुछ नहीं कर पाया। सुरेश के शोर मचाने पर नजदीक काम कर रहे उपप्रधान सतवीर सिंह, सुरजीत सिंह, राकेश कुमार और सरूप सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने पानी में कूद कर दोनों महिलाओं को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला तो दोनों बेसुध थीं। उन्हें तुरंत नूरपुर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए तपोवन में तैयारियां शुरु

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 से 14 दिसंबर तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर डीआरडीए सभागार में उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति की अध्यक्षता में बैठक हुई। इससे पहले प्रशासन की टीम ने विधानसभा परिसर तपोवन में सुविधाओं का जायजा भी लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन, प्रदेश विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा, उपनिदेशक हरदयाल भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी राजेंद्र ठाकुर सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में भी विद्युत, पेयजल इत्यादि की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी विद्युत तथा आईपीएच विभाग के अधिकारियों को कहा गया है। पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का प्लान तैयार कर लिया गया है। साथ ही ट्रैफिक तथा पार्किंग को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ज्वालाजी मंदिर में भक्तों को चांदी के सिक्के देने की तैयारी

द रीव टाइम्स, कांगड़ा

ज्वालामुखी मंदिर में दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को मां ज्वाला के चित्र से अंकित चांदी के सिक्के देने की तैयारी है। ज्वालाजी मंदिर न्यास के सदस्यों ने बैठक में इस संबंध में चर्चा की। उपायुक्त कांगड़ा से अनुमति लेने के बाद इस पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। स्वीकृति मिली तो जल्द ही श्रद्धालुओं को मंदिर में उचित दामों पर मां के चित्र से अंकित चांदी के सिक्के मिलेंगे। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आकर श्रद्धा अनुसार नकदी, सोना व चांदी चढ़ाते हैं। मंदिर न्यास की बैठक में चर्चा की गई कि शक्तिपीठ में जमा चांदी को पिघलाकर चांदी के सिक्के बनाकर श्रद्धालुओं को उचित दामों पर दिए जा सकते हैं। हालांकि, सिक्का कितने ग्राम का होगा या कितने रुपये में मिलेगा, इस पर अभी चर्चा नहीं की गई है। मंदिर अधिकारी बिशन दास शर्मा ने बताया कि जल्द ही डीसी कांगड़ा को इसके बारे में अवगत करवाया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट सदस्य पुजारी प्रशांत शर्मा ने बताया कि बैठक में न्यास सदस्यों, एसडीएम अंकुश शर्मा और मंदिर अधिकारी के साथ इसके बारे में चर्चा हुई है पर डीसी कांगड़ा की स्वीकृति के बाद ही इस पर कार्य किया जाएगा।

सदर विस क्षेत्र में सड़कों पर 90 करोड़ होंगे खर्च

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

सदर बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र की समस्त पंचायतों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा हैं ताकि लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। यह बात सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 9.50 करोड़ रुपये की लागत से कंदरौर-बगड़ी, सलणू-बरमाणा सड़क के विस्तारीकरण कार्य का विधिवत भूमि पूजन करने के उपरांत निचली भटेड़ में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की भाग्य रेखाएं होती हैं तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का व्यापक विस्तार सुनिश्चित किया जा रहा है। हर गांव को सड़क से जोड़ने का संकल्प किया गया है ताकि ग्रामीण विकास के साथ लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो सके। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में लगभग 90 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि सड़कों के विस्तारीकरण तथा मरम्मत पर खर्च की जा रही है जिससे लोगों को गुणवत्तायुक्त बेहतरीन सड़कें प्रदान की जा सकें ताकि छोट-बड़े वाहन चालकों, आम लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

पेड़ कटान मामले में वन विभाग ने बैठाई जांच

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

स्वारघाट कस्बे के समीप कुलाह जंगल से पेड़ काटने के मामले में वन महकमे ने विभागीय जांच बैठा दी है। वन विभाग के जिला बिलासपुर के एसीएफ उक्त सारे मामले की जांच करेंगे। वन विभाग में पूरे मामले की जांच बैठा दी गई है। वन विभाग की पोस्ट स्वारघाट में गत लंबे अरसे से कार्यरत एक फॉरेस्ट गार्ड पर गत दो दिन पहले बिना अनुमति के चार चील के पेड़ और एक सफेदे का पेड़ कटवा देने का मामला उजागर हुआ है। हैरानी इस बात की है कि जो चील के पेड़ काटे गए हैं उन पेड़ों पर वन विभाग की ओर से मार्किंग करके इन्हें फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के सुपुर्द किया जाना था लेकिन उससे पहले ही एक फॉरेस्ट गार्ड ने इनकी बलि चढ़ा दी है। वन परिक्षेत्र अधिकारी स्वारघाट द्वारा उक्त आरोपी वन रक्षक को कार्यालय में तलब किया गया है। हालांकि इसके बाद वन विभाग बिलासपुर के वन मंडलाधिकारी द्वारा भी उक्त मामले पर कड़ा संज्ञान लेते हुए आरोपी वन रक्षक के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। एसीएफ बिलासपुर की ओर से उक्त पेड़ कटान के सारे मामले की जांच की जाएगी।

कायाकल्प संस्थान में हर विस के एक गरीब मरीज का होगा मुफ्त इलाज

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

चिकित्सा केंद्र कायाकल्प पालमपुर ने हर विस से एक गरीब मरीज का अब मुफ्त इलाज होगा। 15 दिन तक उपचार मुफ्त किया जाएगा।

फरवरी तक लोगों को यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए प्रदेश की हर 68 विस क्षेत्रों के भाजपा-कांग्रेस के सभी विधायकों को पत्र भेज दिए गए हैं। विधायकों को यह पत्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और कायाकल्प ट्रस्ट के अध्यक्ष शांता कुमार ने भेजे हैं। यह सुविधा स्वामी विवेकानंद के जन्मोत्सव में 15 नवंबर से 12 फरवरी तक चलने वाले जयंती समारोह के उपलक्ष्य में दी जाएगी।

इसमें हर विधायक अपने विस क्षेत्र से एक अति गरीब व्यक्ति का नाम कायाकल्प

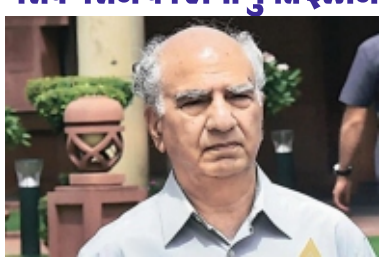

संस्थान पालमपुर को भेजेगा। विधायकों को लिखे पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के हर विस क्षेत्र का विधायक अपने विस से एक अति गरीब व्यक्ति का चयन इलाज के लिए करें, ताकि इस व्यक्ति का इलाज कायाकल्प में किया जा सके। प्राकृतिक चिकित्सका केंद्र कायाकल्प में 15 दिन तक चलने वाले इस व्यक्ति को इलाज से लेकर हर चीज मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएगी।

नादौन में रिवर राफ्टिंग को रोजगार से जोड़ने के होंगे प्रयास-डीसी

द रीव टाइम्स, हमीरपुर

ब्यास नदी तट पर रिवर राफ्टिंग को पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त, एसपी, हमीरपुर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने चंबापत्तन तक राफ्टिंग का आनंद लिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने यहां इस योजना को सफल बनाने के लिए अन्य संभावनाओं का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त हरिकेश मीणा, एसपी अर्जित सेन ठाकुर, एसडीएम नादौन किरण भड़ाना, बीडीओ पारस अग्रवाल, थाना प्रभारी प्रवीण राणा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है।

अभी उत्तराखंड के नितिन को यहां राफ्ट चलाने की स्वीकृति प्रदान की है, परंतु स्थानीय युवाओं को भी इस रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि, नादौन को पर्यटन की दृष्टि से उभारा जा सके।

इसके साथ जुड़े अन्य रोजगार के साधनों को भी विकसित करने की योजना को साकार रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम किरण भड़ाना ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही यह सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। नादौन को पर्यटन की दृष्टि से उभारने के लिए लंबित पड़ी इस योजना पर प्रशासन की ओर से कार्य किया जा रहा है। इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सरकाघाट अस्पताल से चिकित्सकों के तबादले पर भड़के लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

सिविल अस्पताल सरकाघाट में चार चिकित्सकों के तबादलों पर भड़के लोगों ने सोमवार को हिमाचल किसान सभा और अन्य संगठनों के साथ मिलकर आक्रोश रैली निकाली। अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सरकाघाट पुराने बस अड्डे पर एकत्रित होकर लोग प्रदर्शन करते हुए बाजार तक पहुंचे और फिर अस्पताल का घेराव किया। विरोध प्रदर्शन में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा।

प्रदर्शनकारियों ने सरकाघाट अस्पताल में खाली चल रहे चिकित्सकों के पद भरने की गुहार लगाई। साथ ही चेताया कि अगर स्थानांतरित चिकित्सकों के साथ साथ अन्य रिक्त पद नहीं भरे गए तो उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। एसएमओ सरकाघाट के माध्यम से प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री, आईपीएच मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को मांग पत्र भेज कर शीघ्र चिकित्सकों की तैनाती की मांग उठाई। सरकार को चेताया कि यदि शीघ्र तैनाती नहीं हुई तो तीन दिसंबर को सभी संगठन आंदोलन शुरू करेंगे तथा रास्ता रोक कर प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे।

इस अवसर पर दिनेश काकू, रणताज राणा, मोहनलाल, बाला राम, सुरेश, प्रकाश, सूरत, शंभू सकलानी, टेक सिंह, प्रमिला, विद्या, मीना, कौशल्या, ऋत्विक, वरुण, विकास, नरेंद्र, मान सिंह, संतोष, कमला, कंचन, कुंता, रेखा, रेहड़ी यूनियन के राजीव कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

मनरेगा मजदूरों का आरोप, नहीं दी जा रही पूरी दिहाड़ी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

ग्राम पंचायत गरोड़ू में मनरेगा मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पूरी दिहाड़ी नहीं दी जा रही है। मजदूरों ने इसकी शिकायत डीसी से की है। मांग की कि उन्हें पूरी दिहाड़ी दिलवाई जाए। मनरेगा मजदूरों ने एक अधिकारी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

कहा कि उन्हें कम दिहाड़ी दी जा रही है। मनरेगा वर्कर विमला देवी, बुद्धि देवी, व्यास देवी, निक्की देवी, मधु देवी, रीना देवी, कांता देवी, उर्मिला देवी, रुमा देवी, सोमा देवी, गुड्डी देवी, मनसा देवी, कौशल्या देवी, भगती देवी, अंजू, शांता देवी, सीमा शर्मा ने उपायुक्त मंडी से मौजूदा अधिकारी की कार्य प्रणाली की छानबीन करने और उन्हें पूरी दिहाड़ी दिलाने की मांग की है।

अधिवक्ता रजनीश भारती ने बताया कि मनरेगा के तहत भारत सरकार द्वारा हर पंचायत में जरूरतमंद को कम से कम सौ दिन के कार्य देने का प्रावधान है। कनिष्ठ अभियंता फतेह सिंह ने कहा कि कार्य की पैमाइश के हिसाब से पेमेंट करने के आदेश हैं। अगर मनरेगा के तहत कार्य करने वाली लेबर किसी उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवाना चाहे तो करवा सकते हैं।

मनाली तक रेल ट्रैक का रुट फाइनल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

सामरिक महत्व और पर्यटन विकास के लिए बहुप्रतिक्षित 465 किलोमीटर लंबी बिलासपुर - मनाली - लेह रेल लाइन का सर्वे पूरा करने के बाद रेलवे विभाग ने रेलवे ट्रैक को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। विभाग ने रेफरेंस प्वाइंट्स पर जीपीएस के माध्यम से ट्रैक को अंतिम रूप दिया है। इसके साथ - साथ बिलासपुर से मनाली तक रेलवे विभाग ने निशानदेही करते हुए पक्के निशान (बुर्जियां) भी लगाए हैं। नगवाईं में भी बुर्जियां लग चुकी हैं। इस लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे हो चुका है। इस रेल लाइन पर लगभग 83360 करोड़ रुपये का खर्च होगा।

बता दें कि लद्दाख का सुदूर उत्तरी कोना देश की राजधानी दिल्ली से रेल लाइन से जुड़ने जा रहा है। इस रेल सेक्शन का नाम बिलासपुर - मनाली - लेह लाइन रखा गया है। सामरिक रूप से इसका खास महत्व है, क्योंकि लेह से कुछ ही दूरी पर चीन की सीमा पड़ती है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दुनिया की यह सबसे ऊंची रेल लाइन होगी। इस रेल सेक्शन पर ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। इस रेल लाइन के बनने से दिल्ली-लेह के बीच सफर का समय 40 से घटकर 20 घंटे रह जाएगा। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि लोकेशन सर्वे पूरा होने के बाद फाइनल ट्रैक को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में नहीं बजेगी अब देवधुन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

देवी - देवताओं के महाकुंभ अंतरराष्ट्रीय दशहरा में पहली बार बजाई गई देवधुन अब भविष्य में नहीं बजेगी। देवता धूमल नाग की कड़ी आपत्ति के बाद जिला कारदार संघ और आयोजक बैकफुट पर आ गए हैं। देवता ने दशहरा में बजाई देवधुन को देव परंपरा खिलाफ बताया और गूर के माध्यम से देव समाज को आगाह किया वह देव नियमों से बाहर रहकर काम न करें। देवताओं ने रघुनाथपुर में हुई जगती में भी कड़ा एतराज जताया था। कुल्लू दशहरा में इस बार बजाई देवधुन ने वाहवाही लूटी थी। पहली बार 2200 बजंतरियों की उपस्थिति में देवधुन को इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। अब देवधुन पर देवता सहमत नहीं हैं। हालांकि, दशहरा उत्सव के समापन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अगले साल उत्सव में इसे और भी बेहतर बनाने की बात कही है, लेकिन अब धूमल नाग ने देव समाज को देव आदेशों से बाहर न जाकर किसी भी धार्मिक आयोजन न करने की चेतावनी दी है। देव समाज के जुड़े लोगों ने भी देव आज्ञा का पालन करने की हामी भरी है। जिला देवी - देवता कारदार संघ के पूर्व अध्यक्ष दोतराम ठाकुर ने कहा कि देवता ने भविष्य में देवधुन बजाने पर मना किया है।

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

निरीक्षण करने गई टीम पर खनन माफिया ने किया पथराव

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

हिमाचल के कुल्लू जिले के सैंज घाटी की भलाण पंचायत में निरीक्षण करने गई टीम पर खनन माफिया ने पथराव कर दिया। इससे टीम बाल-बाल बच गई और कर्मचारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। भुंतर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दल-बल के साथ मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पत्थर तोड़ने की विस्फोटक सामग्री मिली है। मौके पर देखा खनन तो माफिया ने पहाड़ को खोदकर काफी गहरी टनल बना दी थी। कुल्लू जिले के नदी-नालों से रेत, बजरी और पत्थर निकालने का काम जारी है। सैंज घाटी की भलाण पंचायत के राक्सगाड स्थित हुरख में शुक्रवार को खनन और वन विभाग की संयुक्त टीम निरीक्षण के लिए गई थी। भनक खनन माफिया को इसकी भनक लगी उन्होंने टीम पर पथराव शुरू कर दिया।

ऐसे में टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। इस दौरान एक व्यक्ति ने कर्मचारियों से फोन पर गालीगलौज की और जान से मारने की भी धमकी दी है। टीम में शामिल कर्मचारियों ने इसकी सूचना फोन पर पुलिस अधीक्षक कुल्लू को दी। उन्होंने नजदीकी पुलिस चौकी सैंज से दल-बल के साथ कर्मचारियों को

मौके पर भेजा। पुलिस ने भुंतर थाना में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उधर, पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में नशे की तस्करी और अवैध खनन को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।

पराशर, बरोट, शिकारीदेवी तथा कमरुनाग में ट्रैकिंग पर प्रतिबंध

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

जिला प्रशासन ने सर्दियों में पराशर, बरोट, शिकारीदेवी तथा कमरूनाग में ट्रैकिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त कार्यालय में शरद ऋतु से पहले तैयारियों को लेकर समस्त विभागों की बैठक में जिलाधीश ऋग्वेद ठाकुर ने यह आदेश दिए हैं। उन्होंने पुलिस, पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सर्दियों के दौरान पराशर, बरोट, शिकारीदेवी तथा कमरूनाग जाने वाले पर्यटकों और ट्रैकरों पर नजर रखें। किसी को भी ट्रेकिंग की अनुमति न दें ताकि इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान आपदाओं से निपटने और बेहतर समन्वय बनाने के लिए प्रशासन व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने जिले के समस्त उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे छोटी से छोटी घटना की भी जानकारी जिला प्रशासन को व्हाट्सऐप ग्रुप पर दें। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपे। सर्दियों के दौरान चौहारघाटी, सराजघाटी, शिकारी देवी, कमरूनाग क्षेत्र, रोहांडा, पंढार, बरोट, पराशर थुनाग, जंझैहली तथा गाढ़ागुशैणी सहित अन्य क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना रहती है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से 28 नवंबर तक अपने-अपने विभाग से संबंधित एक-एक अधिकारी का पदनाम और मोबाइल नंबर जिला प्रशासन के पास भिजवाने के निर्देश दिए। रोहांडा से पंढार तक ज्यादा बर्फबारी होने के कारण मुख्य सड़क पर वाहनों की आवाजाही को जारी रखने और चौलचौक क्षेत्र की सड़कों को खुलवाने के लिए उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर को अपने स्तर पर व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 5 दिसंबर तक 5 महीने का राशन भिजवाने की प्रक्रिया होगी पूरी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में स्थित 76 उचित मूल्य की दुकानों में 5 महीने का अग्रिम राशन और गैस सिलिंडर भिजवाने की प्रक्रिया जारी है। तीन महीने का राशन भिजवा दिया गया है। उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में तुरंत जिला आपदा प्रबंधन परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 01905–226201, 202, 203, 204, अथवा टोल फ्री 1077 नम्बर पर सूचित करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

आधा घंटा बंद कमरे में अमिताभ–जयराम में इस खास मुद्दे पर हुई ये बातचीत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदी के महानायक बिग बी से महत्वपूर्ण चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अमिताभ बच्चन से मनाली सर्किट हाउस में करीब आधा घंटा बंद कमरे में चाय की चुस्कियां लेते हुए इस विषय पर चर्चा की।

दरअसल प्रदेश सरकार ने हिमाचल को शूटिंग हब बनाने के लिए कैबिनेट में पॉलिसी बना दी है। इस क्षेत्र में प्रबल संभावनाएं होने के चलते सरकार अब हिमाचल को होटल इंडस्ट्री के साथ फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना से जोड़कर देख रही है। इनवेस्टर्स मीट के बाद इस दिशा में गंभीरता से कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार ने शूटिंग यूनिट के लिए सिंगल विंडो परमिशन समेत कई कारगर कदम उठाए हैं।

विंटर सीजन में फिल्म यूनिट के साथ मनाली आए अमिताभ को सरकार ने स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया। बिग बी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल में फिल्म सीटी बनाने पर विचार कर रही है, ताकि मुंबई से आने वाले फिल्म निर्माताओं को मुंबई की तरह सभी सहूलियतें हिमाचल में मिल सकें। आगे भी फिल्म यूनिटों को सरकार ज्यादा सुविधाएं देगी।

अमिताभ बच्चन ने कहा कि हिमाचल बहुत ही खूबसूरत है। यहां फिल्म शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं। मनाली को उन्होंने इसके लिए

आदर्श स्थल बताया इस दिशा में वह अपने स्तर पर प्रदेश सरकार की हरसंभव सहायता को तैयार हैं।

इस दौरान बिग बी की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध होने से कई लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा।

पंडित जवाहर लाल नेहरु मेडिकल कॉलेज चंबा में तैनात हुए दो नए विशेषज्ञ

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में प्रदेश सरकार ने दो नए नेत्र विशेषज्ञों की तैनाती कर दी है। पिछले डेढ़ सालों से मेडिकल कॉलेज का नेत्र विभाग एक विशेषज्ञ के सहारे चल रहा था। एक विशेषज्ञ मरीजों की जांच करने के साथ ऑपरेशन थियेटर में आंखों के ऑपरेशन भी कर रहे थे। इसके साथ ही ओपीडी, वार्ड राउंड के साथ मरीजों के ऑपरेशन करने में परेशानी आ रही थी। कुछ दिन पहले ही सरकार ने चंबा मेडिकल कॉलेज में दो नए नेत्र विशेषज्ञों की तैनाती की है। अब जिले के छह लाख लोगों की आबादी को नेत्र रोग संबंधित बेहतर सेवाएं मिलेंगी। नए विशेषज्ञों के रूप में डॉ. विनोद धीमान और डॉ. शैलेंद्र मिन्हास ने मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया है। नेत्र ओपीडी में रोजाना 200 से 300 मरीजों की जांच होती है। ऐसे में अब मरीजों को जांच के लिए ओपीडी के बाहर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दो विशेषज्ञ ओपीडी में नियमित रूप से सेवाएं देंगे। पहले से सेवाएं दे रहे नेत्र विशेषज्ञ डॉ. आदित्य कश्यप को दो अन्य डॉक्टरों की तैनाती के बाद कुछ हद तक राहत मिली है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य पुरुषोत्तम पुरी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में दो नए नेत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति हुई है। उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। नेत्र विशेषज्ञ के अलावा भी मेडिकल कॉलेज में अन्य डॉक्टरों की तैनाती हुई है।

सरकार को आईना दिखा अभिभावकों ने खुद तैनात कर दिए पांच शिक्षक

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

गुणात्मक शिक्षा के लिए देश भर में अहम दर्जा रखने वाले राज्य का दंभ भरने वाली हिमाचल सरकार और शिक्षा विभाग को चंबा के अभिभावकों ने आईना दिखाया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संघनी के विद्यार्थियों के अभिभावकों ने खुद ही पांच अध्यापकों का इंतजाम कर लिया है। इस स्कूल में करीब साल भर से प्रिंसिपल, पीजीटी अंग्रेजी, हिंदी, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, आईटी, टीजीटी मेडिकल, ओटी, पीईटी, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और क्लर्क तक का पद खाली है। 203 से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए पढ़ाई के लिए यही एकमात्र स्कूल है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए अभिभावकों ने अपने स्तर पर पांच अध्यापकों की व्यवस्था की है। पंचायत प्रधान याकूब मांगरा और अभिभावक रणधीर चंदेल, हेमराज चंदेल, सतीश कुमार, चौन सिंह, भुट्टो, भीलो राम, अतेह मोहम्मद और सुरेश कुमार बताते हैं कि एक साल से अध्यापकों के पद खाली हैं।

जो अध्यापक स्कूल में तैनात थे, उनका तबादला सरकार ने दूसरी जगह कर दिया। उनके स्थान पर अध्यापकों की नियुक्ति भी नहीं की। ऐसे में अभिभावकों को खुद

अध्यापकों का इंतजाम करना पड़ा है। स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष बिमला देवी ने बताया कि शिक्षा विभाग को एसएमसी की तरफ से कई बार प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन सुनने को कोई भी तैयार नहीं है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जानिए प्रतिकूल कब्जे के बारे में

संपत्ति का मालिकाना हक पाना हर किसी की ख्वाहिश होता है, लेकिन यह स्थिति बहुत मुश्किलों को पार करने के बाद आती है।

क्या है कानून : उदाहरण के तौर पर रमेश कुमार का दिल्ली में घर है, जिसे उन्होंने रहने के लिए अपने भाई सुरेश कुमार को दिया हुआ है। 12 साल बाद सुरेश कुमार को प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है और उसका अपने भाई से झगड़ा होता है तो कानून के मुताबिक पोजेशन सुरेश को मिलेगा। इसके कहते हैं प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन।

हालांकि सामान्य कब्जे की स्थिति में स्वामित्व नहीं मिलता, लेकिन प्रतिकूल कब्जे के मामले में वह संपत्ति के मालिकाना हक पर दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अन्यथा साबित होने तक माना जाता है कि पोजेशन कानूनी है और इसकी इजाजत दी गई है। प्रतिकूल कब्जे के तहत जरूरतें सिर्फ यही हैं कि पोजेशन जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीकों से हासिल न किया गया हो।

लिमिटेशन एक्ट : लिमिटेशन एक्ट, 1963 कानून का अहम हिस्सा है, जो प्रतिकूल कब्जे का विस्तार है। इस कानून में प्राइवेट संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्तियों के लिए 30 साल की अवधि होती है, जिसमें आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। किसी भी तरह की देरी भविष्य में परेशानियां पैदा कर सकती है।

समय अवधि : इस कानून को लागू करने और समयावधि की गणना करने के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर्टी मालिक के पास किस तारीख से है। इस अवधि के दौरान पोजेशन अटूट और बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। दावेदार के पास संपत्ति का इकलौता अधिकार होना चाहिए। हालांकि, लिमिटेशन पीरियड में उस वक्त को शामिल नहीं किया जाता, जिसमें मालिक और दावेदार के बीच लंबित मुकदमेबाजी है। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं।

अगर संपत्ति का मालिक नाबालिग है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या वह सशस्त्र बलों में काम कर रहा है तो संपत्ति पर कब्जा करने वाले प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकते।

पब्लिक नॉलेज : बड़ी संख्या में लोगों को दावेदार के कब्जे के बारे में मालूम होना चाहिए। यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि असली मालिक को यह जानने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए कि उसकी संपत्ति किसी के कब्जे में है और वह वक्त रहते कार्यवाही कर सके। हालांकि असली मालिक को सूचित करने के लिए कोई बाध्य नहीं है।

वास्तविक कब्जा : लिमिटेशन की पूरी अवधि के दौरान वास्तविक अधिकार होना चाहिए। फसल कटाई, इमारत की मरम्मत, पेड़ लगाना और शेड बनाना जैसे शारीरिक कार्यों के जरिए भी वास्तविक कब्जा निर्धारित होता है। संपत्ति पर बिना शारीरिक कब्जा किए कब्जा करने वाला प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकता।

प्रतिकूल कब्जे का दावा करने के लिए अदालत में ये दस्तावेज दिखाने ज़रुरी हैं:

- पोजेशन की तारीख
- पोजेशन की प्रकृति

- पोजेशन के बारे में लोगों को पता है
- पोजेशन की अवधि
- पोजेशन की निरंतरता

जो बदलाव हमें चाहिए : इस पुराने कानून में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि यह इक्विटी के खिलाफ है। यह अतिक्रमियों के बजाय संपत्ति के मालिकों सजा देता है। हालांकि बदलाव होने तक प्रॉपर्टी मालिकों को जागरुक रहकर अपनी संपत्ति पर नजर रखनी चाहिए। अतिक्रमण के किसी भी गैरकानूनी कार्य के खिलाफ समय पर कार्रवाई की जानी जरूरी है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

लिवर ट्रांसप्लांट क्या है ?

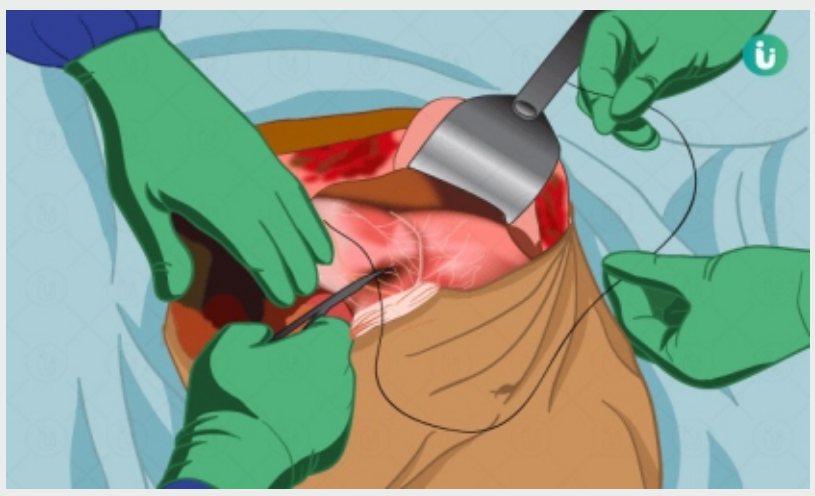

लिवर ट्रांसप्लांट एक विकल्प है और लिवर शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है, जो फिर से बन सकता है। इससे मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट में खराब हो चुके लिवर को सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाता है। इसके बाद उसके स्थान पर पूर्ण स्वथ्य लिवर या स्वथ्य लिवर का आधा भाग मरीज को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है।

किसे होती है जरूरत लिवर शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर के हानिकारक पदार्थों के डी-टॉसीफिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता उन मरीजों को होती है, जिनका लिवर खराब हो चुका हो या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो। ज्यादातर लिवर मृत दाताओं से प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन एक स्वथ्य व्यक्ति भी आधा लिवर दान कर सकता है।

हेपेटाइटिस और सोरायसिस के कारण खराब हो चुके लिवर के रोगियों को भी लिवर प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है। इससे किसी को नया जीवन मिल सकता है।

कौन दे सकता है लिवर

आमतौर पर रोगी को दो तरह से लिवर दिया जा सकता है। पहला परिवार के किसी सदस्य द्वारा लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट से। दूसरा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका मस्तिष्क मृत (ब्रेन डेड) हो चुका हो, ऑर्थोटॉपिक ट्रांसप्लांट या स्पिलिट डोनेशन द्वारा।

इस प्रक्रिया में मृत व्यक्ति के लिवर को दो भागों में बांटकर बड़ा हिस्सा किसी वयस्क व्यक्ति को और छोटा हिस्सा किसी बच्चे को देकर दो जीवन बचाए जा सकते हैं। लिवर निकालने के 6 घंटे के भीतर लिवर ट्रांसप्लांट होना आवश्यक होता है।

लिवर डोनेशन में रखें ध्यान

- डोनर एकदम स्वथ्य हो
- डोनर और मरीज का ब्लडग्रुप समान हो
- डोनर की उम्र 18–60 के बीच हो
- लिवर डोनेशन के पीछे सेवा भाव हो, आर्थिक लाभ नहीं
- डोनर और मरीज के लिवर का आकार सामान हो
- डोनर अगर जीवित है तो डॉक्टर द्वारा बताए गए सारे परीक्षण कराएं
- लिवर डोनेशन के बाद इस तरह रखें खुद का खयाल

आधा लिवर दान करने के बाद आपको कुछ दिनों तक बेहतर देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्जरी के बाद संतुलित आहार लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इससे आप जल्दी रिकवर करते हैं। इस दौरान अत्यधिक भोजन या भोजन के प्रति लापरवाही आपका वजन, उच्च रक्तचाप और शर्करा एंव कोलेस्टॉल बढ़ा सकती है, जो ट्रांसप्लांट किए गए अंग के लिए हानिकारक हो सकता है।

इसके अलावा नियमित चेकअप कराएं और नियमित दिनचर्या के साथ कुछ समय बाद अपने दैनिक कार्यों में जुट जाएं। अंगदान को महादान का दर्जा दिया गया है। इसकी आवश्यकता मरीज को किसी खास अंग के खराब हो जाने, एक्सीडेंट या अन्य किसी बीमारी के कारण नष्ट हो जाने की स्थिति में पड़ती है।

अंगदान मस्तिष्क मृत (ब्रेन डेड) और जीवित दोनों ही डोनर कर सकते हैं। शरीर के कुछ अंग जीवित तो कुछ अंग मृत अवस्था में दान किए जाते हैं लेकिन लिवर को मस्तिष्क मृत (ब्रेन डेड) और जीवित दोनों ही स्थितियों में डोनेट किया जा सकता है।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें:hem.raj@iirdshimla.org

खेल के क्षेत्र में करियर एक बेहतर विकल्प

द रीव टाइम्स ब्यूरो

खेल के क्षेत्र में मिलनें वाले धन और सम्मान के कारण प्रत्येक खिलाडी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना चाहता है, परन्तु उस स्तर तक पहुंचनें के लिए आपको बहुत मेहनत और लगन के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा, भारत सरकार की 'खेलो इण्डिया योजना' के माध्यम से लोगों की रूचि खेल की तरफ बढ़ी है, खेल के क्षेत्र में सिर्फ खिलाड़ी के रूप में ही नहीं बल्कि इससे सम्बंधित अन्य क्षेत्रो में अपना बेहतर करियर बनाया जा सकता है, आप खेल के क्षेत्र में करियर कैसे बना सकते है, इसके बारे में आपको द रीव टाइम्स यहां बताने जा रहा है:

खेल पत्रकारिता में करियर : आजकल टीवी में खेल समाचार को अलग से दिखाया जाता है और प्रतियोगी परीक्षा में इससे सम्बंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए खेल से सम्बंधित सभी गतिविधियों से अपडेट होना अनिवार्य हो गया है, यदि आप खेल की जानकारी रखते हैं तो आप आसानी से इसकी रिपोर्टिंग कर पाएंगे और एक आप एक खेल पत्रकार के रूप में करियर बना सकते हैं।

खेल प्रबंधन : आज के समय में बहुत बड़े - बड़े खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसको सही से संचालित करने के लिए एक मैनेंजमेंट टीम की आवश्यकता होती है, आप इस क्षेत्र में एक मैनेंजमेंट टीम का हिस्सा बन कर अपना करियर बना सकते है। स्पोर्ट्स मैनेंजमेंट में विज्ञापन, बाजार, दर्शक, सुरक्षा आदि शामिल होती है।

स्पोर्ट्स मार्केटिंग : प्रत्येक खेल प्रतियोगिता की सफलता उसके दर्शको पर होती है, मार्केट में खेल को लोकप्रिय बनाना ही स्पोर्ट्स मार्केटिंग कहलाता है, इस कला को समझना आसान नहीं होता है, खेलों की मार्केटिंग करके आप पैसा व पद दोनों को प्राप्त कर सकते है।

फिटनेस एक्सपर्ट : स्पोर्ट्स मैन किसी एथलीट से कम नहीं होते है, वह हमेशा शरीर से फिट रहते है, जिसका लाभ वह किसी फिटनेस सेंटर या हेल्थ क्लब में फिटनेंस एक्सपर्ट के रूप में बन कर प्राप्त कर सकते है। सभी लोग शारीरिक रूप से फिट रहना चाहते है, इसलिए फिटनेस एक्सपर्ट के क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाए बनी हुई और भारत सरकार भी इस पर विशेष ध्यान दे रही है और संयुक्त राष्ट्र ने इसके लिए योग दिवस का आयोजन करता है, योग दिवस भारत सहित विभिन्न देशो में 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में आप फिटनेस एक्सपर्ट के रूप अच्छा करियर बना सकते है।

साइकोलॉजिस्ट के रुप में करियर : प्रत्येक खेल में हार और जीत होती है, जिसका प्रभाव खिलाड़ी के स्वास्थ्य पर बहुत पड़ता है, किसी भी हार के बाद खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने और उसको मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए एक साइकोलॉजस्ट की जरुरत पड़ती है, अतः आप एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपना करियर बना सकते है।

खेल अध्यापक : भारत सरकार खेल को बढ़ावा देनें के लिए सभी विद्यालयों में खेल अध्यापक की नियुक्ति करती हैं, आप स्नातक के पश्चात बीपीएड करने के उपरांत आप किसी विद्यालय में खेल टीचर के रूप नियुक्त हो सकते है, इन दिनों अच्छे स्पोर्ट्स टीचर की खूब डिमांड हो रही

है, स्पोर्ट्स में रूचि रखने वालों के लिए स्पोर्ट्स टीचर एक अच्छा करियर आप्शन साबित हो सकता है।

कमेंटेटर बनकर करियर बनाये : खेल के समय होने वाली कॉमेंन्टेरी को आप ने अवश्य सुना होगा, यदि आप को खेल की अच्छी समझ हैं और आप लम्बे समय तक बिना रुके बोल सकते हैं, तो आपके लिए यह अच्छा पद है, इसमें आपको खेल को और रोचक तरीके से पेश करना होता है, जिससे खेल देख रहे दर्शकों को मनोरंजन के साथ खेल की अहम् जानकारी भी मिल सके, आप क्रिकेट के आलावा अन्य खेलों में कामेंन्टेरी कर के अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

Parameters of Patriotism

In recent episode in Parliament when Sadhvi Pragya, the Member of Parliament representing Bhopal, had called Nathuram Godse as "a patriot", outraged several people in the Parliament. Defence Minister Rajnath Singh had to step in as he criticised the MP's statement as a form of damage control.

"We condemn any philosophy which describes Nathuram as a patriot", Singh had said. He also said that Gandhi's philosophy remained relevant even today and described him as a guide of the nation.

Following the incident, Sadhvi has been dropped from a key parliamentary panel and she has been told not to join the BJP Parliamentary Committee. JP Nadda, the BJP's Working President, also condemned this controversial statement.

The seriousness of the statement can be asserted from the fact that even PM Narender Modi had to step in to condemn it, saying he won't forgive Sadhvi for insulting Bapu.

Now, the question arises whether Nathuram Godse was a patriot or not. If yes, how to logically prove a person to be a patriot who assassinated Gandhi on January 30, 1948, and if not, how to forget all his contributions for India.

In order to reach an agreeable answer, we can start from knowing a bit about early life and political affairs of Nathuram Godse. The available informations show that Godse was an educated, rationalist and logical person with a strong sense of nationalism. His engagement with the contemporary leaders and his involvement in the Indian Freedom Movement cannot separate him from being termed as a 'patriotic'. His boldness, fearlessness, clarity of thoughts and reasonably genuineness, are the traits that point towards him being a 'true patriot'.

Another part is of his disagreement with Gandhi on certain issues. In fact, Gandhi had many times acted as an authoritarian by imposing his views over the majority's consensus and one such example was when everybody in the committee proposed the name of Sardar Vallabh Bhai Patel as the first Prime Minister of the Independent India but Gandhi negated the same and instead supported Nehru for the coveted position. A single man's voice became more vigorous than the voice of the majority.

The same happened in relation with Partition and the associated affairs where many of the ideas and propositions of Gandhi were not digested by the then team members. Nathuram, being bold and action-oriented leader, went uncontrolled and the act which has to be condemned whole-heartedly.

With this background information, it is important to mention about a book 'Gandhi Vadh aur Main' written by Gopal Godse and without reading this book, one cannot objectively judge Godse and his actions. The book presents a number of justifications put forth in the court by Nathuram Godse during his trial. Here the objective of interpretation is whether there was a personal motive of Godse behind murdering Gandhi or the reason was entirely something else. Or was he harbouring any personal ambition which was at risk as long as Gandhi was alive; no part of history reveals that.

It means whatever Godse thought and what he fought for, could have been in the interest of the nation. The disagreement between Godse and Gandhi needs to be seen as personal clashes on thoughts between two individuals striving for common goal. Godse's case, the trial for which took place in Shimla's Peterhoff from 1948-49, was dealt on the basis of the crime he committed; and the corresponding judgement was announced by the then jury. As per my understanding, it seems the argument was not heard in the interest of the nation, had it been so, the court's decision would have been different, which was also influenced by the sentiments of people of newly independent India.

People never came to know that the whole life of Nathuram went towards serving the country. Today, how can we ignore and deny the fact that he dreamt and worked for the nation? Can we revisit and recall the history and omit all his thoughts and actions dedicated for serving the country? If it is not possible to change the facts of history, then taking away the title of a 'patriot' from Nathuram Godse is also not entirely correct.

Yes, he cannot be acquitted for assassinating Mahatma Gandhi, neither this brutality can be justified. But there were a number of patriots who died for the nation in the pre-independence era, such as Lal Bal Pal and many others. There were a number of Freedom Fighters who were not in agreement with Gandhi on many issues, including Netaji Subhash Chandra Bose, all of whom incessantly worked towards realising the dream of Independent India.

Some of the people who witnessed transition from colonised India to free India reveal that majority of the people had felt anger against Gandhi during the partition period. And the composite impact of people's feeling might have created this impact if we see this universe being governed by the law of 'cause and effect'.

It was perhaps the momentary reaction when one community pushed from Lahore, whose lives were destroyed completely, were received in Punjab and Gandhi's 'fast unto death' continued to safeguard the other community in India.

The hesitation of the BJP-led government in Delhi to accept and recognise the contribution of Godse and what all he did for the nation is no less than a sin and disregard towards a great nationalist. People,

the parliamentarians and citizens, who are criticising Sadhvi's remarks on Godse should not look at him as a murderer as it was only incidental with extreme nationalism.

The modern India cannot afford to disown the contribution of Godse, simply on the basis of disagreement between two individuals.

And the disagreement of Gandhi with the common people was perhaps because of the difference on magnitude of the thought process. Gandhi was a cosmic personality and his thoughts were universal, whereas the thoughts of Godse were nationalistic with confinement to the territory of India. The basis of Gandhi's thought was humanity, equality and non-violence. Whereas, Godse's was justice, equality and rationality. When a person is beyond the crude selfishness with the sense of renunciation, he/she starts attaining cosmic consciousness. "This sometimes creates differentiation with those who are concentrating on the territorial priorities. When it comes to the politics, territorial priorities become vigorous than the universal common good influenced by the saintly attributes. And this is also not necessary that a saint is always right, because this process of evolution towards perfection takes ages and until the absolute level of perfection is achieved the shortcomings and weaknesses don't get vanished entirely. For any saint, the ego of leading virtuous life also sometimes becomes terrible weakness. But still, Gandhi was unquestionably a Khshattriya Dharm Sadhak who continued fighting with his inner enemies, such as the senses, until he liberated from his body."

The essence of the matter is that the violent measure adopted by Godse against the peace-loving Gandhi cannot be justified, nor the cosmic stature of Gandhi can ever be underestimated. But the objectiveness and rationality require to justify whether Godse deserves to be labelled as a patriotic or not…!

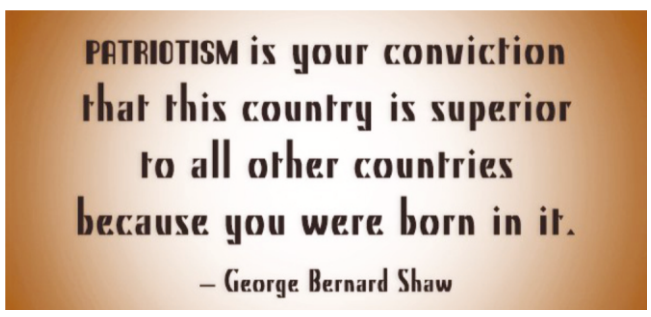

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

सियासत की शहमात में लालची राजनीति का स्यापा

महाराष्ट्र में नैतिक मुल्यों को ताक पर रख चुहा बिल्ली की दौड़ / जनादेश पर भारी भानुमति का पिटारा

जनता के नौकर बताएं जनता किसकी जिम्मेवारी है?

लोकतंत्र की एक सुव्यवस्थित शैली होती है जिसमें समस्त मानक तय होते हैं। राजनैतिक व्यवस्था हमारे इसी ढांचे का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें हमारे प्रतिनिधि संसद और विधानसभा में जाकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जनहित में कानून बनाते हैं, उन्हें पास करते हैं, योजनाओं का निर्माण होता है। हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं और सेवादार बनकर पांच वर्षों के लिए प्रयासरत रहना होता है। कितनी विडंबना है कि आज ये बातें लिखने और पढ़ने तक सिमटती जा रही है।

आज जन प्रतिनिधि सेवक नहीं बादशाह से भी उपर है और उसके हाथ वोट लेने तक ही बंधे होते हैं। जीतने के बाद उसके हाथ ऐसे खुलते हैं कि फिर नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। जनता बस मुंह ही देखती रह जाती है। कुछ कहने का अधिकार उसे नहीं रह जाता है। सत्ता की चाह और लालच इन माननीयों को इतना गिरा देता है कि वो अपनी जिम्मेवारी को ही नहीं समझ पाता है। महाराष्ट्र के संदर्भ में जो हुआ और हो रहा है उससे इन माननीयों के कारण षर्मिंदा ही होना पड़ रहा है। 24 अक्तुबर 2019 को चुनाव परिणाम के बाद अब दिसंबर चल रहा है। तब से अब तक उठापठक जारी है। हालांकि अब सरकार का गठन हो चुका है लेकिन अस्थिरता का दाग इसे भी लगातार परेशान कर रहा है।

सरकार न बना पाने के कारण महाराष्ट्र की जनता को जो नुकसान हुआ उसका ख़ामियाज़ा कौन पूरा करेगा? कभी राजनैतिक दलों के सियासी दांव और कभी राष्ट्रपति शासन, जनता को पता ही नहीं लगा कि ये सब क्या हो रहा है। आख़िर जनता का षासनादेष किसको और किस प्रकार का था?

शिवसेना ने पलटी बाजी, विचारधारा नहीं कुर्सी ही मछली की आंख

महाराश्ट्र में 24 अक्तुबर को आए चुनावी परिणामों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को जनता ने स्पश्ट शासनादेश दिया। कांग्रेस और एनसीपी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाए। ऐसे में यह तय हो गया था कि बीजेपी और शिवसेना पूर्ण बहुमत के साथ सरकार का गठन करेंगे। लेकिन शिवसेना ने परिणाम आने के तुरंत बाद पासा पलट कर रख दिया। उन्होंने बीजेपी से उप-मुख्यमंत्री के अलावा अढाई साल के लिए मुख्यमंत्री का पद भी मांग लिया।

इसके लिए उन्होंने देवेन्द्र फडनवीस और गृहमंत्री अमित शाह के साथ इस प्रकार के समझौते का ज़िक्र करते हुए वादा निभाने की बात कही। यहीं से महाराश्ट्र की सियासी चालें चलनी शुरु हुई और उसके बाद तो जनता इसी प्रतीक्षा में रह गई कि कब सरकार का गठन हो और विकास के कार्य आरंभ हो सके। लेकिन शिवसेना ने इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाकर अड़ियल रवैया अपनाकर रखा। उधर देवेन्द्र फड़नवीस और अमित शाह ने स्पश्ट कर दिया कि शिवसेना के साथ ऐसा कोई भी वायदा नहीं था और फड़नवीस के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ें गए थे। शिवसेना ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद पलटी खाई और शिवसेना की ओर से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को अढाई साल के लिए मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने रख दी। इस पेंतरे से बीजेपी सकते में आ गई क्योंकि ऐसी शर्त मानोगे तो भी और न मानोगे तो भी.... बीजेपी की सियासी हार तो निश्चित ही थी।

लेकिन बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि वो मुख्यमंत्री के पद पर समझौता नहीं करेंगे। अब शिवसेना ने संजय राउत को आगे कर चालें चलनी शुरु कर दी। बाला साहेब ठाकरे के मातोश्री में जहां सरकारों के आने-जाने का दस्तूर रहता था, वहां सत्ता के मोह ने उद्धव ठाकरे को शरद पवार और सोनिया गांधी के छत की सीढ़ीयां चढ़वा दी। सत्ता के लिए उद्धव ने हिंदुत्व और सेक्युलेरिज़्म की ऐसी खिचड़ी पकाई कि पत्रकारों के जवाब देते समय कुर्सी हिल गई। उहापोह की स्थिति में शिवसेना के तथाकथित चाणक्य संजय राउत ने तो आग में घी डालने का कार्य जारी रखा ही किंतु अमर्यादित भाषा के साथ बीजेपी को चोटिल करते रहे। ऐसे में बीजेपी ने अंत तक शिवसेना की प्रतीक्षा की लेकिन इस बार शिवसेना मातोश्री से ही मुख्यमंत्री की मांग पर अडिग रही।

इसके लिए शिवसेना ने एन सी पी और कांग्रेस पर खूब डोरे डाले। एक समय में बाला साहेब ठाकरे ने कट्टर हिंदुत्व की बात करते हुए सोनिया गांधी के बारे में ऐसे शब्द कह दिए थे कि जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने गठबंधन को दरकिनार करते हुए हर संभव सत्ता को ही चुना। महाराष्ट्र से लेकर हर ओर इस बात की खूब आलोचना हुई कि एक विचारधारा की पार्टी किस प्रकार तिलांजली देकर अपने ही धुर विरोधियों की गोद में जाकर बैठ गई। इन चुनावों में कांग्रेस और एनसीपी के ख़िलाफ शिवसेना सीमा से बाहर जाकर विरोधी शब्दों का उपयोग किया था।

उधर कांग्रेस ने अपनी हेकड़ी बदस्तूर जारी रखी और शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार की दौड़ लगवाई। लेकिन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी।

बीजेपी ने लगाई लंबी छलांग लेकिन अंगूर खट्टे ही निकले

बीजेपी ने बड़ा दांव चला और एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार को 35–36 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ अपनी ओर मिला लिया जिसे बीजेपी यह कह कर पल्ला झाड़ती रही कि अजित पवार खुद आये थे समर्थन पत्र लेकर बीजेपी के पास। आनन-फानन में राष्ट्रपति शासन हटाकर तड़के ही देवेन्द्र फड़नवीस ने सरकार बनाने की समर्थन पत्र सौंप कर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अजित पवार को उप - मुख्यमंत्री बना दिया। पूरे महाराष्ट्र में सबको हैरत में डाल दिया।

अमित शाह की चाणक्य नीति किसी की समझ में नहीं आई। एनसीपी में टूट हो गई और शरद पवार के लिए चुनौती भी। लेकिन एक बार फिर शरद पवार का पावर स्ट्रोक काम कर गया और सभी एनसीपी विधायक जो अजित पवार के साथ चले गए थे, वापिस शरद पवार के साथ लौट आए। अंततः अजित पवार भी वापिस चाचा की गोदी में ही बैठ गए। बीजेपी की फज़ीहत का यह आलम था कि देवेन्द्र फड़नवीस को इस्तीफ़ा देना पड़ा। सरकार फिर से गिर गई। इसी ड्रामे के बीच एक नया गठबंधन तैयार हुआ जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बीजेपी की चाल के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सभी निर्वाचित विधायकों को होटल में क़ैद कर दिया गया तथा होटल से लेकर सभागारों तक उनकी सुबह - शाम परेड होती रही।

ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर पर शपथों का दौर चलता गया। बीजेपी मात्र मूक दर्शक ही बनी रही क्योंकि कोई और चारा भी नहीं था। सबसे बड़े दल के रुप में महाराष्ट्र में विजयी होने के बाद भी शिवसेना ने विपक्ष में बैठने के लिए मज़बूर कर दिया। उधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बार-बार कहते गए कि मैं बाला साहेब ठाकरे के प्रति समर्पण की भावना से उद्धव ठाकरे और षिवसेना को कुछ नहीं बोलूंगा।

उधर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि शिवसेना ने धोखा दिया और शिवसेना ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़े, आदित्य ठाकरे ने भी मोदी के पोस्टर लगाए और अंत में पीठ में छूरा घोंप कर औकात दिखा दी। लेकिन, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी को महाराष्ट्र में अपने ही दांव-पेंच भारी पड़ गए और मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र में सरकार न बना पाने के कारण अब बीजेपी को भगवारंग भी सिमटता जा रहा है। धीरे-धीरे बड़े राज्यों से सत्ता से हाथ धोने पड़ रहे हैं। क्षेत्रिय दलों ने बीजेपी के रथ को रोकने का भरसकर प्रयास जारी रखा है।

शपथ समारोह में वैधानिक चूक

बीजेपी के लोटस टारगेट से घबराये तीनों दलों ने शीघ्रता से सरकार के गठन के लिए दावा किया और विधायकों को शपथ दिलवाकर उद्धव ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री की शपथ ली।

शपथ लेने से पहले संविधानिक ग़लती कर दी जिससे फज़ीहत तो हुई ही साथ ही इसे संविधान के जानकारों ने बड़ी भूल करार दिया। शपथ में पहले दलों के नेताओं के संबोधन पर राज्यपाल कोश्यारी ने भी फटकार लगाई और भविष्य में इसे सुधारने के लिए कह दिया। उद्धव मातोश्री से सीधे निकलकर विधानसभा पहुंचे हैं।

बाला साहेब ठाकरे के रौब चादर और शिवसेना की बेबाकी का दामन थामे सत्ता की पेचिदगियों की समझ आने में अभी समय लग जाऐगा क्योंकि व्यवस्था से बाहर रहकर चीखने और कोसने में तथा व्यवस्था का हिस्सा बनकर उसे दुरुस्त करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। उद्धव को परिपक्वता दिखाने की आवश्यकता है न कि बचकाना ब्यान और हरकतों से वैधानिक पद को ठेस पहुंचाने की। यहां उद्धव ठाकरे सामना के लेखक नहीं और शिवसेना के प्रमुख भी नहीं, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है जिन्हें सबको साथ लेकर चलना होगा और प्रतिद्वंद्वियों के साथ सामजस्य बैठाकर प्रदेश हित में विनम्र होकर काम करने की आवष्यकता रहेगी।

हल्दी की गट्ठी से पंसारी की दुकान तक

शिवसेना ने सत्ता की कुर्सी को मातोश्री तक पंहुचाकर बीजेपी को बैकफुट पर तो ला ही दिया साथ ही अपने धुर-विरोधियों को साथ लेकर एक लंबे अस्थिरता के माहौल को स्थिर भी कर दिया। ये अलग बात है कि ये स्थिरता कितने दिन तक रहेगी इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में ही है।

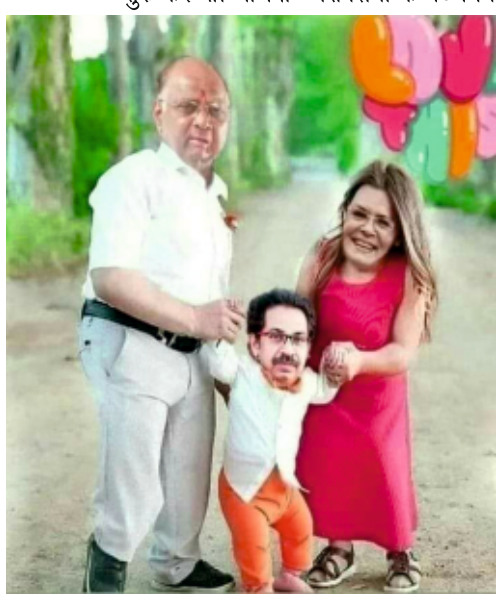

शिवसेना में सबसे बड़ी भूमिका में संजय राउत की रही जिसने बीजेपी को षुरु से अंत तक कोसने का काम किया। इतना ही नही अपने बड़बोलेपन और बेतुके ब्यानों के कारण शिवसेना का उच्च रक्तचाप घटता - बढ़ता भी रहा। अंततः सरकार के गठन के बाद भी संजय राउत ने बीजेपी को खरी-खोटी सुनानी बंद नहीं कि और शिवसेना ने एक प्रकार से अधिकारिक रुप से ब्यानबाजी करते हुए कह दिया अगला लक्ष्य गोवा है। गोवा में बीजेपी की सरकार है जिसे शिवसेना ने कहा कि वो सरकार शीघ्र ही गिरा दी जाऐगी तथा वहां भी हमारा गठबंधन ही सरकार बनाऐगा। हालांकि कि शिवसेना की यह बात समझ से परे हैं।

इसका क्या आधार है.... यह भी वो स्पष्ट नहीं कर पाये। इतना ही नहीं शिवसेना की ब्यानबाजी तो यहां तक है कि गोवा में सरकार गिराने के बाद देश के अन्य राज्यों में भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हरसंभव कोशिश जारी रहेगी।

यहां यह कहना ग़लत नहीं होगा कि शिवसेना को जो हल्दी की गट्ठी मिली उससे वो पंसारी की दुकान चलाने की सोच रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति इतनी सरल भी नहीं जितना उसे शिवसेना मान कर चल रही है। सभी को पता है कि मुख्यमंत्री बेशक़ उद्धव ठाकरे हो, सत्ता की चाबी शरद पवार के हाथ ही रहेगी। उस पर कांग्रेस की बैसाखी को भूलना मूर्खता होगी। कांग्रेस का पुराना इतिहास है, सत्ता में बिठाना और गिराना चुटकी का काम है। और यहां तो मजबूरी की इंतहा है।

जितनी चाबी भरी कांग्रेस ने, उतनी चले शिवसेना...

शिवसेना को अपनी जुबान पर लगाम के साथ - साथ परिपक्कवता दिखानी होगी क्योंकि जनता तो सिर्फ भुगतने के लिए ही है, पर जब चाबी जनता के हाथ आती है तो वर्तमान को अतीत बनने में अधिक समय नहीं लगता है।

इस सरकार पर सबकी निगाहें है कि क्या यह सरकार पांच वर्श पूरा भी कर पाऐगी कि नहीं? क्योंकि भानुमति का पिटारे में कई पेंच, कब्जे, कील, जोड़ और तारें हैं जिनको समेट कर रखना चुनौती से कम नहीं है।

आख़िर जनता की जिम्मेवारी किसकी है?

महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उससे आम लोग भी यह सोचने पर विवश है कि सत्ता के लिए अंधी दौड़ में आम से माननीय बनाने वाली जनता के साथ ये धोखा क्यों और कब तक? जनता ने जो आदेश अपने मतों के आधार पर दिया, उसका सरेआम उल्लंघन करते हुए अपनी सत्ता भूख को शांत करने के उद्देश्य से ये जनादेश की अवमानना और राज्य को बेसहारा छोड़ने की इजाज़त इन सत्ताधीशों को किसने दी?

महाराष्ट्र में दो गठबंधनों ने चुनाव लड़ा जिसमें एक गठबंधन को जनता ने स्वीकारते हुए जनादेश प्रदान किया और दूसरे गठबंधन को सत्ता की रेस से बाहर करते हुए बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रखा। जैसे ही परिणाम आए, इन लालची दलों ने जनता के जनादेश को दरकिनार करते हुए अपनी गाटियां खेलनी आरंभ कर दी और प्रदेष के विकास को रोक कर चुहा - बिल्ली की दौड़ शुरु कर दी। बीजेपी - शिवसेना के गठबंधन को बहुमत प्रदान कर प्रदेश के विकास की जिम्मेवार सौंपी थी जिसमें शिवसेना ने इसे नकार कर जनादेश को दरकिनार कर दिया। लेकिन देर से ही सही, सरकार का गठन हो चुका है और जनता अब विकास के लिए प्रतीक्षारत है। यहां केवल महाराश्ट्र की ही बात नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इसी उठापठक के बीच नेताओं का सत्तामोह जनता पर भारी पड़ रहा है।

जनता की सुनवाई हो, ऐसा भी संभव नहीं दिखता। अब इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि विधानपालिका के संरक्षक ही जब तक लार टपकाना बंद नहीं करेंगे और राष्ट्रहित में जनमानस की आवाज़ नहीं बनेंगे, माहौल बदलने वाला नहीं है। पांच वर्शों में एक बार वोट हासिल करने के लिए हाथ जोड़कर, पैरों पर गिर कर जनता को गुमराह करते हुए सत्तासीन होते ही अंगुठा दिखाना, इनकी फितरत में शामिल है जिसे जनता मूक रह कर देख और सह रही है। सत्ता और दलों के बीच एक बड़ी दूरी करने की बात ही यदि नेताओं के लिए मानक बन जाए तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करना ही न पड़े।

लेकिन सत्ता तक की पहुंच कहीं न कहीं निजी स्वार्थ के अलावा राजनैतिक दलों को मज़बूत और संबल करने की चेष्ठा और कर्म जनता के साथ विश्वासघात की तरह है और जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका भी। जनता इन दावंपेचों को जिस दिन समझ गई, उसके बाद काली रोटी पर सफेद रुमाल अधिक समय तक नहीं रह पाऐगा।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

मौलिक कर्त्वयों को अधिकारों के साथ जोड़ना जरुरी : राज्यपाल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समरोह 26 नंवबर को गयेटी थियेटर में आयोजित किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय समरोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे जबकि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने इस अवसर पर कहा कि यह हमारे संविधान की विशेषता है कि इसने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की उन्नति में प्रमुख भूमिका निभाई है। डॉ. भीम राव अम्बेडकर के भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण योगदान से भारत के नागरिक लाभान्वित हुए हैं। भारतीय नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता देने के लिए भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान को अपनाने के बाद देश के नागरिकों ने नए संवैधानिक, वैज्ञानिक भारत में प्रवेश किया जिसने शान्ति, नम्रता और विकास का सूत्रपात किया।

दत्तात्रेय ने कहा कि भारतीय संविधान समस्त विश्व के लिए एक विशिष्ट दस्तावेज है, और इस महान योगदान देने के लिए बाबा सहिब को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमारा संविधान नागरिकों के कर्त्तव्यों और अधिकारों में सन्तुलन बनाए रखता है जो हमारे संविधान की विशेषता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मौलिक कर्त्तव्यों पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। समाज में तब तक प्रजातंत्र की पूर्ण स्थापना संभव नहीं जब तक नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों को उनके अधिकारों के साथ न जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 1949 में आज ही के दिन भारत के संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया। संविधान दिवस आयोजित करने का उद्देश्य भारतीय संविधान के महत्व और इसके रचनाकार डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।

पुलिस आरक्षियों के एक हजार रिक्त पद भरे जाएंगे: मुख्यमंत्री

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रिज मैदान में हिमाचल प्रदेश पुलिस स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रदेश में शांतिपूर्ण तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रदेश पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है तथा प्रदेश को अपनी मूल्यावान सेवाएं प्रदान कर रही है। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को बेहतर प्रदर्शन तथा कुशल बनाने के लिए आधुनिक सूचना साधन उपलब्ध किए है। प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा उन्हें सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गुड़िया हेल्पलाइन 1515 और शक्ति बटन ऐप को आरम्भ किया है। उन्होंने पुलिस विभाग से प्रदेश में नशे से सम्बन्धित गतिविधियों पर निगरानी रखने कहा ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर पुलिस विभाग को सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने एक हजार पुलिस कर्मियों के रिक्त पद भरने करने की घोषणा की। उन्होंने पुलिस विभाग की मांग के अनुरूप सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व पुलिस कर्मियों को एक पदोन्नति देने की भी घोषणा की। उन्होंने हिमाचल पुलिस की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सभी पुलिस कर्मियों को विशेष मेडल देने की घोषणा की।

250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई ने हाईकोर्ट को सौंपी जांच रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल में 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सिर्फ 22 शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित किए जाने के मामले में सीबीआई ने सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश कर दी है। जनहित में दायर याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि घोटाले में 2772 शैक्षणिक संस्थान हैं, लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ 22 की ही जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा। सीबीआई की ओर से अदालत से गुहार लगाई गई थी कि चूंकि वह मामले कि जांच कर रही है तो इस स्थिति में सीबीआई को सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दायर करने की अनुमति दी जाए, ताकि उनके द्वारा की गई जांच सार्वजनिक न हो। दूसरी ओर सीबीआई ने चंडीगढ़ स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सर्कल कार्यालय से घोटाले से संबंधित जमा राशि का रिकॉर्ड एकत्र किया। इसके लिए सीबीआई की एक टीम चंडीगढ़ गई और वहां से यह टीम इससे संबंधित रिकॉर्ड एकत्र कर शिमला लाई है। पिछले दिनों ही सीबीआई ने शिमला में बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की है।

सीबीआई विभिन्न बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाने जा रही है। इनमें से कई से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है और उनकी गवाही ले चुकी है। अब कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद इनसे वहां भी गवाही ली जाएगी।

सरकारी व निजी भूमि चिन्हित करने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित होगी कमेटी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक एवं अन्य इकाइयों को स्थापित करने के उद्देश्य से सरकारी व निजी भूमि चिन्हित करने के लिए संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिम प्रगति पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हो चुके हैं, उन्हें शीघ्र स्वीकृतियां प्रदान करना सुनिश्चित बनाएं। उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन जैसे प्रमुख विभागों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन्हें तय समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने विशेषकर वन स्वीकृतियों के समयबद्ध निपटारे पर बल देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि निवेशकों को स्वीकृतियां प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उन्होंने कहा कि हिम प्रगति पोर्टल की सुविधा आरम्भ होने से पहले निवेशकों को अपनी परियोजनाओं को स्वीकृत करवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। विभिन्न क्षेत्रों में निवेश से प्रदेश के विकास में सहयोग मिलता है इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार निवेशकों को हरसंभव सहायता प्रदान करे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए हिम प्रगति पोर्टल बहुत उपयोगी साबित हो रहा है क्योंकि इससे परियोजनाओं की तीव्र स्वीकृतियां सुनिश्चित हो रही हैं। निवेशक इसके माध्यम से अपनी परियोजनाओं पर हो रही प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने निवेशकों को आह्वान किया कि इस पोर्टल के माध्यम से अपनी समस्याएं सामने रखें ताकि उनका समयबद्ध निपटारा हो सके।

हिमाचल में अब मिला मिलेगी विटामिन 'ए' और 'डी' युक्त फोर्टिफाइड दूध

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने यहां टाटा ट्रस्ट और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से हिमाचल प्रदेश दूध प्रसंघ के विटामिन 'ए' और 'डी' से युक्त फोर्टिफाइड दूध 'हिम गौरी' का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए फोर्टिफाइड दूध का इस्तेमाल विश्व भर में किया जाता है। सामान्य दूध की तुलना में इस दूध के अनेक लाभ हैं। यह गाय का ऐसा दूध है जिसमें अतिरिक्त विटामिन और खनिज होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी है। यद्यपि आज बाजार में उपलब्ध ज्यादातर खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान की जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि दूध का इस्तेमाल मुख्यतः बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए किया जाता है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इसमें सभी जरूरी सामग्री हो।

जय राम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत मिल्कफेड वर्ष 2020 में मण्डी और शिमला जिला के दत्तनगर में दो नए दूध प्रसंस्करण प्लांट स्थापित करने जा रहा है। इससे प्लांट की क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

तीन मई को होगा नीट, ऑनलाइन आवेदन शुरु

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नीट -2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार एम्स और जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च (जीपमर) के लिए भी नीट से ही एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें भरी जाएंगी। आवेदन करने के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की है। नीट का प्रवेश परीक्षा 3 मई 2020 को ली जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। परीक्षा पैन, पेपर बेस्ड ली जाएगी। प्रवेश परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 1500 रुपये, आर्थिक कमजोर और ओबीसी के लिए 1400 रुपये और एससी, एसटी व अन्य वर्ग के लिए 800 रुपये फीस निर्धारित की गई है।

आवेदन की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 27 मार्च से निकाले जा सकेंगे। प्रवेश परीक्षा का परिणाम 4 जून को वेबसाइट पर डाला जाएगा। अभ्यर्थी की आयु परीक्षा तिथि तक 17 से 25 साल होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल तक है।

अभ्यर्थी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायो टेक्नॉलॉजी और अंग्रेजी विषय के साथ इंटर में न्यूनतम 50 फीसदी अंक होने चाहिए।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 फीसदी अंक अनिवार्य हैं। मेडिकल जमा दो की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। नीट का पेपर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 11 भाषाओं में होगा।

प्रदेश में नीट के लिए हमीरपुर और शिमला जिले में ही केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थी नीट का ऑनलाइन फार्म लोकमित्र केंद्रों में जाकर भर सकते हैं। नीट की अधिक जानकारी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी(एनटीए) की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

सरकारी विक्रय केंद्रों में नहीं बिकेंगी कीटनाशक व खरपतवार की दवाइयां

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक खेती में ढालने के लिए कृषि विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। कृषि विभाग ने सरकारी विक्रय केंद्रों पर कीटनाशक और खरपतवार की दवाइयां न बेचने का फैसला लिया है। कीटनाशक की दवा न बेचने के बारे में कृषि विभाग ने सभी विक्रय केंद्रों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें इसी फसल अर्थात अभी से कीटनाशक तथा खरपतवार की दवाई न बेचने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश सरकार ने कृषि विक्रय केंद्रों पर इन दवाइयों का स्टॉक नहीं भेजा है। वहीं, अब किसानों को इन्हीं दवाइयों को खरीदने के लिए प्राइवेट डीलरों के पास लुटने को मजबूर होना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग अब प्रदेश के किसानों को अपने विक्रय केंद्रों पर किसी भी प्रकार की कीटनाशक तथा खरपतवार दवाइयां मुहैया नहीं करवाएगा।

कृषि विभाग इसका कारण प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना बता रहा है, लेकिन प्रदेश के किसानों को यही दवाइयां निजी दवा विक्रेताओं के पास आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, जहां वह अब किसानों से मनमाफिक दाम वसूलने से गुरेज नहीं करेंगे।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

भरे जाएगें 3000 से अधिक पद

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में जे.बी.टी, सी. एण्ड.वी. और टी.जी.टी. श्रेणियों के 3636 पद भरने का निर्णय लिया गया। ये पद भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इनमें 684 पद टीजीटी कला, 359 टीजीटी नॉन-मेडिकल, 261 टीजीटी मेडिकल, 1049 शास्त्री, 590 भाषा अध्यापक तथा 693 जेबीटी के शामिल हैं।

लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना

मंत्रिमंडल ने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 के मध्य प्रजातंत्र की रक्षा और लोगों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों को आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (एमआईएसए) तथा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल (डीआईआर) के तहत हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना, 2019 को क्रियान्वित करने की भी स्वीकृति दी गई।

गरीबों को रोजगार पैकेज

जो परिवार वित्तीय कठिनाई से गुजर रहे है उन्हें केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैकेज देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मिशन अंतोदय लागू करने को स्वीकृति दी। इस कार्य के लिए ग्रामीण विकास विभाग एक लाख परिवारों का सर्वेक्षण करेगा और यह जानने के प्रयास करेगा कि क्या ये परिवार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं अथवा नहीं। दूसरे चरण में इन परिवारों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा जबकि तीसरे चरण में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया जाएगा।

आईजीएमसी और नेरचौक में कोकलीयर इम्पलांट

मंत्रिमण्डल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला, डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज टांडा तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में कोकलीयर इम्पलांट सेंटर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिले के सिराज विकास खण्ड के जैंशला गांव में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र को खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पदों को सृजित कर भरने की अनुमति दी गई।

अन्य फैसले

मंत्रिमण्डल ने मनाली एग्लोमरेशन कुल्लू घाटी क्षेत्र के लिए विकास योजना संशोधन को सहमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण मण्डल किलाड़ के नियंत्रण में चल रहे सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल किलाड़ का नियंत्रण को चम्बा जिले के तीसा स्थित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल भंजराडू को सौंपने का निर्णय लिया। इसे पदों सहित आईपीएच मंडल को हस्तांतरित किया जाएगा। इस निर्णय से सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के किलाड़-पांगी उप-मण्डल की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा।

मंत्रिमण्डल ने यमुना नदी में हिमाचल प्रदेश के जल के हिस्से को ताजेवाला कॉरीडोर में भुगतान के आधार पर बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी अपनी अनुमति प्रदान की। इससे प्रदेश सरकार को सालाना 21 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

मण्डी जिला के सरकाघाट तहसील के श्री नबाही देवी मन्दिर को हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक स्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 में लाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से अब इस मन्दिर का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होगा।

शिमला जिला में सीमेंट उद्योग स्थापित करने तथा चूना पत्थर और खादान खनिजों के निष्कर्षण के लिए मै. डालमियां सीमेंट (भारत) लिमिटेड के पक्ष में तीन वर्ष के लिए लैटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र) को स्वीकृति दी गई है।

लोक निर्माण विभाग के वास्तुकार विंग में सीधी भर्ती से अनुबंध आधार पर बैच वाईज विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

यूपी विधि आयोग ने की सिफारिश धर्मांतरण रोकने हेतु बनेगा कठोर कानून

द रीव टाइम्स ब्यूरो

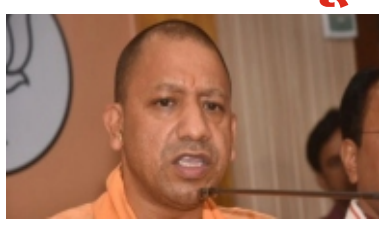

उत्तर प्रदेश में विधि आयोग की सिफारिशों के मुताबिक, यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए शादी कर रहा है, तो उसे सात साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं यह शादी भी अवैध मानी जाएगी। विधि आयोग ने इसके लिए 'उत्तर प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2019' का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री को दे दिया है। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि यदि किसी ने दूसरा धर्म अपना लिया था लेकिन वे अपने पुराने धर्म में दोबारा लौटना चाहता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को 'घर वापसी' के नाम से जाना जाता है।

असम सरकार प्रत्येक दुल्हन को 10 ग्राम सोना देगी

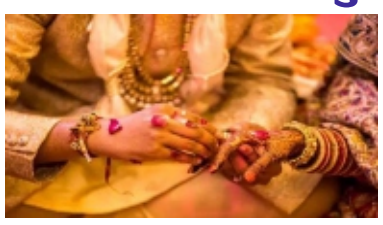

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अरूंधति योजना के तहत असम सरकार दुल्हल को उपहार देगी। जिसने कम से कम 10वीं की पढ़ाई की है और अपनी शादी को पंजीकृत कराया है। असम राज्य के वित्त मंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि 'अरुंधति स्वर्ण योजना' का लाभ पाने के लिये कुछ अन्य शर्तें भी हैं। योजना का लाभ उठाने हेतु दुल्हन के परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए दूल्हा कि आयु 21 वर्ष ओर दुल्हन की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

01 दिसंबर से सभी वाहन मालिकों के लिए फास्टैग अनिवार्य

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मंत्रालय ने डिजीटल भुगतान को प्रोत्साहन देने तथा पारदर्शिता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा की सभी लेनों को 01 दिसंबर 2019 से 'फास्टैग लेनों' के रुप में घोषित करने का आदेश दिया है। फास्टैग का मुख्य उद्देश्य रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए अधिसूचित दरों के अनुसार उपयोग शुल्क एकत्र किया जा सके। फास्टैग का उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि टोल प्लाजा पर रुकने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भुगतान की सुविधा के कारण किसी को भी नकदी रखने की आवश्यकता नहीं है।

मनु भाकर ने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मनु भाकर ने जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 244.7 अंक का कुल स्कोर बनाया। मनु भाकर आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के दस मीटर एयर पिस्टल इवेंट में हीना सिद्धू के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। हालाँकि, मनु भाकर और राही सरनोबत महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में क्वालीफाई करने में असफल रही। मनु भाकर ने 583 अंक के साथ इस इवेंट में 10वें स्थान पर रहीं, वहीं सारनोबत 569 अंक के साथ 18वें स्थान पर रहीं।

सड़क हादसों में तमिलनाडु पहले स्थान पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 के मुकाबले साल 2018 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 0.46 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर में भी 2.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में साल 2010 तक दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग, देश के कुल सड़क नेटवर्क में एनएच की हिस्सेदारी मात्र 1.94 फीसदी ही है जबकि कुल सड़क दुर्घटनाओं में इसकी हिस्सेदारी 30.2 प्रतिशत है। अन्य सड़कें, जो कुल सड़कों का करीब 95.1 प्रतिशत हैं, क्रमशः 45 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 38 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार थी।

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019 संसद द्वारा पारित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का न्यास के पदेन सदस्य होने का हक समाप्त हो जायेगा। उसकी जगह पर लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता को सदस्य बनाया जायेगा। राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 के अंतर्गत प्रावधान था कि इसके न्यासी कांग्रेस प्रमुख होंगे।

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने संसद में कहा कि सरकार स्वतंत्रता आंदोलन के सभी शहीदों को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह संशोधन उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जलियांवाला बाग ट्रस्ट की स्थापना साल 1921 में की गई थी और जनता द्वारा वित्त पोषित किया गया था।

मलयालम कवि अक्कितम को मिला 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 की घोषणा हो चुकी है, इस वर्ष यह पुरस्कार मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी को दिया जाएगा। प्रख्यात ओडिया लेखिका प्रतिभा राय की अध्यक्षता में एक निर्णायक मंडल ने उनके नाम की घोषणा से पहले एक बैठक की। निर्णायक मंडल के अन्य सदस्य थे शमीम हनफी, सुरंजन दास, माधव कौशिक और डॉ. पुरुशोत्तम ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपये, वाग्देवी की एक मूर्ति, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह शामिल हैं। अक्कितम मलयालम कविता जगत में एक प्रसिद्ध लेखक हैं।

उनका जन्म 1926 में हुआ था और उनका पूरा नाम अक्कितम अच्युतन नंबूदरी है, लेकिन वे अक्कितम के नाम से लोकप्रिय हैं। उन्हें बचपन से ही साहित्य और कला में रुचि थी। कविता के अलावा, अक्कितम ने नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं।

डेविड एटनबरो को मिला इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह जानकारी इंदिरा गांधी स्मारक न्यास के सचिव ने 19 नवंबर 2019 को दी। डेविड एटनबरो का जन्म 08 मई 1926 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उन्होंने ब्रॉडकास्टर प्रकृतिवादी प्रस्तुतकर्ता के तौर काफी काम किया है।

उन्होंने वर्षों तक, अपने कार्यक्रमों और पुस्तकों के माध्यम से, हमारे ग्रह पर जीवन की महिमा के सामान्य लोगों की पीढ़ियों को शिक्षित किया है।

केंद्र सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए भारतीय पोषण कृषि कोष की शुरुआत की

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्र सरकार ने कुपोषण से निपटने के लिए भारतीय पोषण कृषि कोष की शुरुआत की है। इसके लिए भारत में 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध प्रकार की फसलों का भंडार होगा। कोष का मुख्य उद्देश्य देश भर में महिलाओं और बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना है, जिसमें कृषि सहित बहु-क्षेत्रीय परिणाम आधारित रूपरेखा शामिल है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से भारतीय पोषण कृषि कोष की शुरुआत की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय पोषण कृषि कोष परियोजना के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है।

भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी एआईबीए की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी एशियाई संघ का प्रतिनिधित्व करेंगी। अनुभवी मुक्केबाज उन छह मुक्केबाजों में शामिल थे, जिन्हें पांच महाद्वीपों से आयोग के सदस्यों के रूप में चुना गया था। इस आयोग में पांच क्षेत्रीय संघों एशिया, ओसनिया, यूरोप, अमेरिका और यूरोप से एक महिला और एक पुरुष मुक्केबाज को चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आईओसी) एक अंतरराष्ट्रीय समिति है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैण्ड के लॉजेन में स्थित है। सरिता देवी साल 2000 में एक पेशेवर मुक्केबाज बन गई थीं। वे मणिपुर पुलिस में डीएसपी हैं। उन्हें साल 2009 में 'अर्जुन पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था।

केंद्रीय गृह ने लद्दाख क्षेत्र के लिए विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लद्दाख में तापमान की गिरावट के साथ सर्दियों में सामान्य डीजल जम जाता है। इस डीजल के जमने से गाड़ियों को चलाने में बहुत परेशानी होती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसे ध्यान में रखते हुए विशेष विंटर ग्रेड डीजल का उत्पादन शुरू किया। इस विंटर ग्रेड डीजल से अत्यधिक ठंड के समय पर्यटकों को यात्रा के दौरान आसानी होगी। इस विंटर ग्रेड डीजल से क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यह डीजल - 33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी नहीं जमता है।

ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में दक्षिण एशिया में बांग्लादेश शीर्ष पर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में सूचकांक में बांग्लादेश का कुल रिस्क स्कोर 72 है जो पिछले वर्ष की तुलना में दो अंक ज्यादा है। इस सूची में बांग्लादेश को 178वां स्थान मिला है तथा भारत को 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश में सबसे ज्यादा रिश्वत लेन-देन की संभावनाएं मौजूद हैं। इसमें इस वर्ष 200 देशों की सूची जारी की गई है। दक्षिण एशिया के भूटान में रिश्वतखोरी का आशंका सबसे कम है। भूटान को इस सूची में 52वें स्थान पर रखा गया है।

न्यूजीलैंड को इस सूची में पहले स्थान पर है तथा सोमालिया 200वें स्थान पर रखा गया है। जिस देश को इस सूची में सबसे ज्यादा रैंकिंग दी गई है वे सबसे अधिक प्रभावित देश है।

मिशन गगनयान: रुस में प्रशिक्षण के लिए 12 संभावित यात्रियों का चयन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल के अनुसार, इसरो के पहले मानव मिशन गगनयान हेतु अंतरिक्ष यात्रियों का चुनाव पेशेवर तरीके से किया जा रहा है। भारतीय वायु सेना के बारह लोगों को गगनयान परियोजना हेतु संभावित यात्री के तौर पर चुना गया है। अंतरिक्ष यात्रा हेतु भारतीय वायु सेना के कर्मियों के चयन की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो चुका है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान है। गगनयान मिशन के अंतर्गत करीब दस हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

जेयर बोल्सोनारो होंगे भारत में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री मोदी ने जेयर बोल्सोनारो को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है। इस निमंत्रण को ब्राजील के राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। प्रोटोकॉल के मुताबिक, गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि का पद भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। भारत का विदेश मंत्रालय मुख्य अतिथि किस देश की हस्ती को बुलाया जाएगा, इसके लिए वह विभिन्न पहलुओं की जांच करता है। बोल्सोनारो सरकार ने हाल ही में ब्राजील घूमने हेतु भारतीयों के लिए वीजा की आवश्यकता खत्म कर दी है।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस: 2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा तथा असमानता से बचाने एवं उन्हें उनके अधिकार दिलाने हेतु मनाया जाता है। यह दिवस 80 देशों में 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। साल 2007 में भारत ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया था। भारत में इसके बाद से ही प्रत्येक साल 19 नंवबर को यह दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस के दिन पुरुषों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

गोतबया राजपक्षे बने श्रीलंका के राष्ट्रपति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

गोतबया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बनें हैं। बहुसंख्यक सिंहली बौद्ध उन्हें युद्ध नायक मानते हैं, जबकि बहुसंख्यक तमिल अल्पसंख्यक उन्हें अविश्वास से देखते हैं। वे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति तथा मौजूदा विपक्ष के नेता महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई है। गोतबया राजपक्षे ने साल 1983 में मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। जब श्रीलंका ने साल 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के साथ अपना युद्ध समाप्त किया था तब वे रक्षा विभाग के प्रमुख रहे थे।

सरकार ने मणिपुर में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने मणिपुर में लोकटक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार लंबे समय से इस परियोजना के विकास की मांग कर रही थी। इस परियोजना के विकास की मांग लोकटक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एल सुसिन्द्रो मेइती द्वारा शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को मंजूरी देने से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत 25.58 करोड़ रुपये है। यह पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और पर्यटन क्षेत्र को भी एक बड़ा बढ़ावा देगा। यह क्षेत्र में परिवहन का सबसे सस्ता साधन होगा। इसमें दुर्घटना की संभावना भी कम है इसलिए यह सड़क और रेल की तुलना में अधिक सुरक्षित है। इस योजना को इस आधार पर अनुमोदित किया गया है कि यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसका प्रवाह प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित नहीं करेगा। लोकटक झील मणिपुर के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। लोकटक झील मोइरांग, मणिपुर में स्थित है। यह झील तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप हैं जो हर साल सैकड़ों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। झील 980 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैली हुई है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अमेरिकी चेतावनी के बावजूद तुर्की ने किया रुसी एस-400 का परीक्षण

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका की कड़ी आपत्ति और प्रतिबंधों की चेतावनी के बावजूद तुर्की ने हाल ही में रूसी एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण शुरू कर दिया। यह परीक्षण अमेरिकी लड़ाकू विमान एफ-16 के मुख्य ठिकाने मर्टेड मिलिटरी बेस पर किया जा रहा है। माना जा रहा है कि परीक्षण में अमेरिकी लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया जा सकता है। तुर्की अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य संगठन का इकलौता मुस्लिम सदस्य देश है। उल्लेखनीय है कि भारत ने भी रूस से इसी डिफेंस सिस्टम की खरीद का समझौता किया है। तुर्की को रूसी सिस्टम की पहली बैटरी जुलाई में मिली थी, तुर्की की सेना को इसका प्रशिक्षण और परीक्षण अब किया जा रहा है। अमेरिका को आशंका है कि रूसी सिस्टम के इस्तेमाल से उसकी संवेदनशील तकनीक की गोपनीयता खत्म हो जाएगी।

एफ-35 जैसे अमेरिकी अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के तकनीक रहस्य रूस के पास पहुंच जाएंगे। वहीं, इस खतरे से बचने के लिए पहला कदम उठाते हुए अमेरिका ने तुर्की को एफ-35 विमान बेचने की प्रक्रिया रोक दी है। तुर्की ने अमेरिका से 100 एफ-35 विमान की खरीद का सौदा किया था। सौदे में तकनीक की सीमित साझेदारी का भी समझौता हुआ था। अमेरिका ने रूस के साथ हथियारों और सैन्य जानकारी के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना रखा है। इसी कानून के आधार पर उसने तुर्की को चेतावनी दे रखी है।

इसी कानून का हवाला देकर अमेरिका ने भारत पर भी दबाव बनाया है। भारत ने भी रूस के साथ एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद का सौदा किया है। 2021 में इसकी पहली बैटरी की आपूर्ति होनी है।

120 साल पुराने दो मंजिला लाइट हाउस को पहियों के सहारे किया गया शिफ्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

डेनमार्क में 120 साल पहले समुद्र किनारे लाइट हाउस बनाया गया था। 1990 में जब इस लाइट हाउस को जलाया गया था, उस समय समुद्र से इसकी दूरी 660 फीट थी। अब समुद्र से इसकी दूरी मात्र 20 फीट रह गई है। प्रशासन का कहना है कि यदि इसको अभी यहां से शिफ्ट नहीं किया जाता तो अगले कुछ सालों में समुद्र इसे अपने पानी में समा ले जाता। इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इस वजह से अब इसको यहां से शिफ्ट करने की योजना बनाई गई और तकनीकी की मदद से अब समुद्र 260 फीट की दूरी पर शिफ्ट कर दिया गया। डेनमार्क में इस लाइट हाउस को 120 साल पहले बनाया गया था। अब इसे यहां से शिफ्ट करने के बाद फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसे Rubjerg Knude लाइट हाइस के नाम से जाना जाता है। अब इसे समुद्र की सतह से 260 फीट दूर ले जाकर वहां शिफ्ट कर दिया गया। इसे शिफ्ट करने के बाद एग्टवेज के द्वीप पर जटलैंड में फिर से रोशन कर दिया गया। नए तरीके से इसे नीली रोशनी से रोशन किया जा रहा है। नई जगह पर खोले जाने के बाद अब इसे देखने के लिए भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस ऐतिहासिक इमारत को शिफ्ट करने के लिए जब काम शुरू किया गया तो इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आसपास जमा थे। वो ये देखना चाह रहे थे कि इसे

किस तकनीक से और कैसे यहां से शिफ्ट किया जाएगा। इमारत को शिफ्ट करने के काम में लगे लोगों ने इस इमारत के तीन ओर से एक बेरिकेड लगा रखा था जिससे प्रत्यक्षदर्शी इसके पास न पहुंच सके। लाइट हाउस को जैसे-जैसे शिफ्ट करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा था वैसे-वैसे लोग इसे देखकर खुश हो रहे थे।

पाक-चीन और श्रीलंका की तिकड़ी से सतर्क हुआ भारत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी हाल ही दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए श्रीलंका में गए। इस यात्रा में दोनों मुल्क क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता होगी। गौरतलब है कि गत माह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपने पद की शपथ ली थी। कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान विदेश मंत्री की यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों कि श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन का ट्राएंगल भारत के लिए सही नहीं है। राष्ट्रपति गोतबाया का चीन प्रति दिलचस्पी जग जाहिर है। ऐसे में यह बात तब और अहम हो जाती है, जब श्रीलंका की मौजूदा सरकार का रुख भारत विरोधी रहा है।

ऐसे में इस यात्रा पर भारत की भी नजर रहेगी। हालांकि, नए राष्ट्रपति से संपर्क साधने में भारत ने बहुत तत्परता दिखाई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर गोतबाया से मुलाकात करने वाले पहले विदेशी उच्चाधिकारी रहे। जयशंकर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए शुभकामना पत्र के साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को भारत दौरे का निमंत्रण भी दे आए। उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। वह इसी हफ्ते बतौर राष्ट्रपति अपने पहले विदेशी दौरे के रूप में भारत आएंगे। इससे पहले चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एलान किया था कि वह नहीं चाहते कि उनका देश किसी तरह की क्षेत्रीय शक्ति खींचतान में शामिल हो। इसे उनके चीन के साथ कथित झुकाव का जवाब माना गया। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोतबाया का चीनी प्रेम के चलते भारत की यह चिंता लाजमी है। इसका प्रमाण यह है कि भारत के तमाम विरोध के बावजूद रक्षा मंत्री के रूप में गोतबाया ने चीनी युद्धपोतों को कोलंबो बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद महिंद्रा राजपक्षे ने भी वर्ष 2014 के चुनाव में अपनी हार का ठीकरा भारतीय खुफिया एजेंजियों के सिर फोड़ा था।

इस्लामाबाद म्यूजियम में रखी गई बुद्ध की दुर्लभ कलाकृति, स्वात घाटी से खोजी गई थी मूर्ति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के म्यूजियम में भगवान बुद्ध के सिर की एक दुर्लभ कलाकृति प्रदर्शन के लिए रखी गई है। स्वात घाटी क्षेत्र से खोदाई में मिली इस कलाकृति को मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना कहा जा रहा है।

तीसरी से चौथी सदी के दौरान निर्मित इस कलाकृति को बीती सदी के छठे दशक में इटली के पुरातत्वविद गिसेप तुसी ने खोजा था। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद म्यूजियम के निदेशक अब्दुल गफूर लोन ने कहा, 'स्वात के चूना पत्थर से बनी भगवान बुद्ध की यह मूर्ति दुर्लभ है। इसमें बुद्ध के सौम्य चेहरे और जूड़े में बंधे बालों को दर्शाया गया है। प्राचीन काल में हमलावरों से बचाने के लिए ऐसी मूर्तियों को बौद्ध मठों के अंदर जमीन में गाड़ दिया जाता था।'उन्होंने कहा कि आमतौर पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां तक्षशिला और अफगानिस्तान में पाई जाती हैं। स्वात से मिली इस कलाकृति में उनके बालों को सिर पीछे की ओर लपेटा गया है। झुकी हुई आंखें और सौम्य चेहरा इसे उनकी अन्य मूर्तियों से विशिष्ट बनाता है। लोन ने कहा, 'आमतौर पर बुद्ध की प्रतिमाओं में उनके कानों में कुंडल देखे जाते हैं पर इस कलाकृति उनके कान सामान्य हैं।

कुषाण काल से संबंधित यह असाधारण कलाकृति बौद्ध स्तूप से भी पुरानी है।' प्रदर्शनी में इसके अलावा टेराकोटा से बनी बुद्ध की तीन अन्य कलाकृतियां भी प्रदर्शित की जा रही हैं। तीनों दुर्लभ कलाकृतियां दूसरी से तीसरी सदी हैं। उनकी खुदाई ब्रिटिश

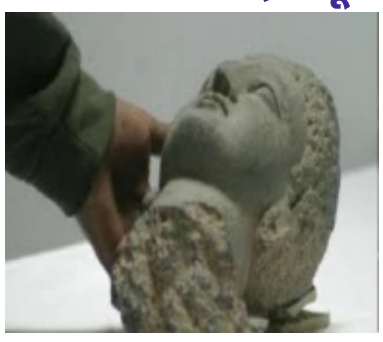

पुरातत्वविद सर जॉन मार्शल ने की थी। इनमें शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में बुद्ध के सिर को तराशने पर विशेष ध्यान दिया गया है और महीन सामग्री का भी उपयोग किया गया है। लोन ने कहा, 'जब हूणों ने बौद्ध मठों और स्तूपों को जला शुरू कर दिया था तो लोगों ने इन्हें जमीन के नीच दफनाकर संरक्षित करने का प्रयास किया था।

पूर्व क्रिकेटर और स्पिन के जादूगर मुथैया मुरलीधरन ने संभाली नई जिम्मेदारी, बने श्रीलंका में गवर्नर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

श्रीलंकाई क्रिकेट के दिग्गज और स्पिन के जादूगर मुथैया मुरलीधरन ने नई जिम्मेदारी सभाली है। श्रीलंका के नव नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा उन्हें श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के राष्ट्रपति की नई सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन नए राज्यपालों में शामिल हैं, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में अपना कार्यभार संभाला। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति राजपक्षे ने मुरलीधरन को उत्तरी प्रांत के गवर्नर का पद स्वीकार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति सचिवालय के सूत्रों ने दैनिक को बताया कि पूर्व स्पिनर को उत्तरी प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। जबकि अनुराधा यमपथ को पूर्वी प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया जाएगा और तिस्सा विथारना उत्तर मध्य प्रांत के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेगी। अनुराधा यमपथ राष्ट्रवादी उद्यमी संघ की अध्यक्ष और एक प्रतिष्ठित परिधान निर्यात कंपनी की निदेशक हैं।

अटक गई चीन की सांस, ट्रंप ने हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के समर्थन देने वाले कानून को दी मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बीजिंग की आपत्तियों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने वाले कानून पर हस्तक्षार कर दिए। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अब हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम, 2019 कानून बन गया है। यह कानून मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रतिबंधों का उपबंध करता है। कांग्रेस ने एक दूसरा विधेयक भी पारित किया है, जिस पर ट्रंप ने भी हस्ताक्षर किए हैं।

इसके तहत भीड़ नियंत्रण की गतिविधियों जैसे आंसू गैस, काली मिर्च, रबर बुलेट आदि को हांगकांग पुलिस के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, मैंने इस विधेयक पर राष्ट्रपति शी और हांगकांग के लोगों के सम्मान के लिए हस्ताक्षर किए है। उन्होंने कहा, कानून को इस उम्मीद से बनाया जा रहा है कि चीन अपने अड़ियल रुख का त्याग करेगा और हांगकांग के नेता और प्रतिनिधियों से सौहार्द्रपूर्ण ढंग से अपने मतभेदों को सुलझा सकेंगे। इस बिल पर ट्रंप के हस्ताक्षर के पूर्व चीन ने कई बार इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर सीनेट से पारित हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम, 2019 बिल को रद्द करने की मांग की थी। उसने चेतावनी भी दी थी कि अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

2020 में भी सबसे खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सूची में पाकिस्तान, कई अन्य देश भी शामिल

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आतंकियों की पनाहगाह बना पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एक स्टडी में सामने आया है। यह शोध इंटरनेशनल एसओएस कंपनी ने किया है जो कि रिस्क एडवाइस्ड कंपनी है। यह कंपनी हर वर्ष दुनिया के उन मुल्कों का जायजा लेती है जहां पर सैलानियों के खतरा अधिक होता है।

वहां पर सुरक्षा के अलावा मेडिकल और रोड सेफ्टी पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कंपनी ने जो ताजा सूची जारी की है उसमें 13 देशों का नाम शामिल है। यह सभी देश 2020 में भी सबसे खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको यहां पर ये भी बता दें कि कुछ माह पहले ही अमेरिका के अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव जेम्स मेटिस ने भी पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। यह कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह की किसी सूची में शामिल किया गया है।

वर्ष 2016 में रिचेस्ट डॉटकॉम ने जो सूची जारी की थी उसमें भी पाकिस्तान को खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया था। इसी वर्ष वीरिस्क मैपलक्राफ्ट एजेंसी ने अपराधिक सूचकांक के आधार पर खतरनाक देशों की सूची जारी की थी जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया था। इस एजेंसी ने सूची बनाने से पहले दुनिया के 198 देशों के बारे में अलग-अलग क्षेत्रों का आंकलन किया था।

बहरहाल, फिलहाल जो सूची जारी हुई है उसमें जो 13 देश शामिल किए गए हैं उसमें ज्यादातर अफ्रीकी देश हैं। इस सूची में सात अफ्रीका के पांच, मध्य एशिया के पांच, पूर्वी एशिया के दो और यूरोप का एक देश शामिल है। इस सूची में सबसे ऊपर जिस देश का नाम है वो माली है।

इसके बाद लिबिया, फिर नाइजीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, दक्षिण सूडान, सोमालिया, यमन, सीरिया, अफगानिस्तान, यूक्रेन, इराक, इजरायल और अंत में पाकिस्तान का नाम शामिल है। आपको इस सूची के अब मायने समझा देते हैं

शिनजियांग के हिरासत शिविरों पर चीन का झूठ आया सामने, लोगों पर होता है अत्याचार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अशांत शिनजियांग प्रांत में चल रहे हिरासत शिविरों से जुड़े दस्तावेजों के प्रकाश में आने के बाद चीन घिरता दिख रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इन शिविरों में उइगर बंदियों पर कई तरह की बंदिशों से चीन की यह बात गलत साबित होती दिखती है, जिसमें वह इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र बताता है। लंदन में चीनी दूतावास ने हालांकि इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए मनगढ़ंत और फर्जी बताया है।

दूतावास की ओर से कहा गया कि हिरासत शिविरों से जुड़े ऐसे कोई भी दस्तावेज और आदेश नहीं हैं। इस प्रशिक्षण केंद्रों को आतंकवाद की रोकथाम के लिए स्थापित किया गया है।

दरअसल, ये दस्तावेज इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आइसीआइजे) द्वारा हासिल किए गए थे और विश्व के 17 प्रतिशिठत मीडिया संस्थानों द्वारा प्रकाशित किए गए। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि हिरासत शिविरों में रखे गए लोगों पर टॉयलेट जाने के दौरान भी सख्त निगरानी रखी जाती है। उन्हें एक-दूसरे से मिलने भी नहीं दिया जाता है। दस्तावेजों में उन दिशा-निर्देशों की सूची भी शामिल है जो इन शिविरों को चलाने के लिए शिनजियांग सिक्योरिटी चीफ द्वारा 2017 में जारी की गई थी।

इससे पता चलता है कि इन शिविरों में रखने के लिए पुलिस किस तरह डाटा संग्रह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का इस्तेमाल करती है। दिशा-निर्देशों में हिरासत शिविरों को लेकर अधिकारियों को सख्त गोपनीयता बरतने का भी आदेश दिया गया था। इसके तहत शैक्षिक क्षेत्र में कर्मचारियों के मोबाइल फोन और कैमरा लाने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिस दिन को सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों की स्मृति में समर्पित किया गया है – 17 नवंबर
- भारत ने हाल ही में 2,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली जिस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल रात्रि परीक्षण किया है – अग्नि-2
- प्रतिवर्ष जिस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है – 16 नवंबर
- हाल ही में जिस राज्य में 12 दिवसीय नदी उत्सव 'ब्रह्मपुत्र पुष्करम उत्सव' का आयोजन किया गया – असम
- वह वरिष्ठ पत्रकार जिसने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है – रजत शर्मा
- केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस राज्य में लोअर दिबांग घाटी में सिसेरी नदी पुल का उद्घाटन किया – अरुणाचल प्रदेश
- जो भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी AIBA के पहले एथलीट आयोग में सदस्य के रूप में चुनी गई हैं – सरिता देवी
- जिसे हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुना गया है – गोतबाया राजपक्षे
- यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी पोषण और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्ष से छोटे जितने प्रतिशत बच्चे कम वजन से ग्रसित हैं – 33 प्रतिशत
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जिस क्षेत्र के लिए पहले विंटर ग्रेड डीजल बिक्री केन्द्र का शुभारंभ किया – लद्दाख
- कतर और जिस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में दोहा में पांच दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया है – भारत
- आईएमडी की नवीन विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत छह स्थान फिसलकर जितने पायदान पर आ गया है – 59वें
- हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन जिस शहर में किया गया था – नई दिल्ली
- जिस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा पाकिस्तान को FATF की कार्य योजना लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की पेशकश की गई है – EU
- वह देश जिसने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नए टाइफाइड वैक्सीन की शुरुआत की है – पाकिस्तान
- भारत सरकार द्वारा सभी वाहनों को FASTag लगवाने के लिए जो समयसीमा तय की गई है – 01 दिसंबर
- हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में जल प्रबंधन के लिए 91 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये – कर्नाटक
- जिस सरकारी संस्था द्वारा "नये भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियां ब्लॉकों" का निर्माण नामक रिपोर्ट जारी की गई है – नीति आयोग
- अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 19 नवंबर
- हाल ही में जिस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन – 1 मिसाइल का परीक्षण किया – पाकिस्तान
- भारत और जिस देश के बीच भारी तनाव के चलते बंद की गई पोस्टल सेवाओं को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है – पाकिस्तान
- अखिल भारतीय बाघ अनुमान के चौथे चक्र के अनुसार, आंध्र प्रदेश और जिस राज्य में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है – तेलंगाना
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक में वर्ष 2040 तक सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 495 गीगावाट से बढ़ाकर जितने गीगावाट करने का अनुमान लगाया गया है – 3142 गीगावाट
- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के अनुसार, पिछले पांच दशकों में भारतीय तट पर समुद्र के जल स्तर में जितने सेमी की बढ़ोतरी हुई है – 8.5 सेमी
- इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए जिसे चुना गया है – डेविड एटनबरो
- हाल ही में जारी 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं – 2018' रिपोर्ट के अनुसार जिस राज्य में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई है – तमिलनाडु
- IRCTC ने लग्जरी गोल्डन चौरियट ट्रेन के संचालन और प्रचार के लिए जिस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं – कर्नाटक
- हाल ही में जारी 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं – 2018' रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में जितना प्रतिशत वृद्धि हुई है – 0.46 प्रतिशत
- जर्मनी ने हाल ही में जिस वर्ष तक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जलवायु संरक्षण अधिनियम पारित किया है – 2030
- हाल ही में संपन्न वर्ल्ड पैरा एथेलटिक्स चौंपियनशिप-2019 में भारत जो स्थान पर रहा – 24वें
- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के जितने केन्द्रीय उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है – पांच
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश यात्राओं से जुड़े तथ्य छिपाने हेतु जिस राज्य के विधायक रमेश चेन्नामनेनी की नागरिकता रद्द कर दी है – तेलंगाना
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जिस देश के क्रांजी युद्ध स्मारक का दौरा किया – सिंगापुर
- जिस अभिनेत्री ने एक फिटनेस और जीवनशैली के अग्रणी ब्रांड के साथ मिलकर 'शी गाट री' नामक अभियान शुरू किया है – कैटरीना कैफ
- श्रीलंका में जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है – महिंद्रा राजपक्षे
- हाल ही में जिस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि के चंद्रमा की पहली ग्लोबल जियालॉजिक मैपिंग पूरी की है – NASA
- भारत में जिसे PETA पर्सन ऑफ द इयर चुना गया है – विराट कोहली
- अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लॉन्च किये गये पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम है – अरुण भूमि
- भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने ISSF विश्व कप फाइनल में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल वर्ग में जो पदक जीती है – स्वर्ण पदक
- हाल ही में जिस राज्य में लॉ कमीशन ने जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी है – उत्तर प्रदेश
- हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का जो स्थान है – सातवां
- नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किये गये पहले इलेक्ट्रिक विमान का यह नाम है – X&57 मैक्सवेल
- डीआरडीओ ने हाल ही में अपने जितने पेटेंट्स को औद्योगिक संगठनों के लिए निःशुल्क घोषित कर दिया है – 450
- वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में 01 जनवरी 2020 से सिंगल-यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है – केरल सरकार
- असम सरकार ने राज्य के प्रत्येक दुल्हन को जितने ग्राम सोना उपहार देने की घोषणा की है – 10 ग्राम
- विश्व मत्स्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 21 नवंबर
- वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के इरादे से भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद के साथ समझौता किया – आंध्र प्रदेश सरकार
- भारत और जिस देश के पर्यावरण वैज्ञानिक दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने हेतु मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं – ब्रिटेन
- वह खिलाड़ी जिन्होंने स्कॉटिश ओपन 2019 का पुरुष एकल खिताब जीता है – लक्ष्य सेन
- वह राज्य जिसने हाल ही में फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए तीन सप्ताह का एक विशेष अभियान आरम्भ किया है – उत्तर प्रदेश
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को स्वास्थ्यप्रद भोजन विकल्पों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इस नाम से अभियान आरंभ किया है – ईट राइट अभियान
- वह राज्य जिसने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की – मध्य प्रदेश
- वह राज्य जहां संगाई उत्सव मनाया जाता है – मणिपुर
- वह महिला खिलाड़ी जिसको 'वर्ल्ड एथलीट ऑफ द इयर 2019' खिताब से सम्मानित किया गया है – दलिला मुहम्मद
- वह शहर जिसके द्वारा वर्ष 2020 से सर्कस में जंगली जानवरों के उपयोग पर पूरी तरह पाबंदी लगाए जाने की घोषणा की गई है – पेरिस
- वह स्थान जहां पाए जाने वाले दो सींग वाले अंतिम गैंडे की हाल ही में मृत्यु हो गई है – सुमात्रा
- वह क्रिकेट अंपायर जिसके द्वारा लिखित पुस्तक 'Finding the Gaps' का हाल ही में विमोचन किया गया – साइमन टॉफेल
- हाल ही में जिसने तत्काल प्रभाव से जी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है – सुभाष चंद्रा
- हाल ही में जिस शहर में भारत के पहले सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो-इंडिया समिट – 2019 का आयोजन किया गया – नई दिल्ली
- हाल ही में जिस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों के लिये आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है – छत्तीसगढ़ सरकार
- हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में जिस देश के साइबर अपराध संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है – रूस
- भारत और जिस देश ने अपने द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अनुमोदन पत्र का आदान-प्रदान किया है जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे – अफगानिस्तान
- भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 26 नवंबर
- जिस देश में मौजूद 'फ्लोटिंग स्कूल प्रोजेक्ट' को हाल ही में आगा खां आर्किटेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया – बांग्लादेश
- जिस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाये जाने की घोषणा की गई है – छत्तीसगढ़
- भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जिस दिन मनाया जाता है – 26 नवंबर
- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों हेतु राज्य आकस्मिक निधि से जितने करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी – 5,380 करोड़ रुपये
- इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किये गये भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट – 3 को जिस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है- पीएसएलवी-सी – 47
- "मा गृधः कस्यस्विद्धन" किसका आदर्श वाक्य (motto) है जिसे हाल ही में जारी किया गया है – लोकपाल
- सुधीर धर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है – कार्टूनिस्ट
- हाल ही में राष्ट्रपति ने जिस विधानसभा द्वारा पारित पत्रकार एवं पत्रकारिता संस्थान (हिंसा और संपत्ति की क्षति की रोकथाम) 2017 को स्वीकृति दे दी है – महाराष्ट्र विधानसभा
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के एक अध्ययन के अनुसार, जिस देश के किशोर अन्य देशों के किशोरों की तुलना में अधिक सक्रिय हैं – भारत
- जिस देश ने हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिकी राजदूत को तलब किया – चीन
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को सरकारी आवास में जितने साल तक रहने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है – एक साल
- हाल ही जिस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं – चीन
- हाल ही में जिस देश के द्वारा भारत को अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग से इनकार करने के मामले को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के समक्ष उठाया है – पाकिस्तान
- पाकिस्तान सेना के प्रमुख का यह नाम है जिनके कार्यकाल विस्तार की अधिसूचना को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निलंबित कर दिया गया है – कमर जावेद बाजवा

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- हिमाचल में आउटडोर जिम की शुरूआत किस अभियान के तहत की जा रही हैं – फिट इंडिया के तहत
- हिमाचल में किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली प्रसिद्ध है – निरमंड
- हिमाचल में प्रदूषित नदियों को साफ करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है – 2021 तक
- हाल ही में धर्मशाला में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में संयुक्त अरब अमीरात ने किस क्षेत्र में निवेश करने के लिए रूचि दिखाई है – फल एवं खाद्य
- घेपन देवता का मंदिर कहां स्थिति है – लाहौल-स्पीति
- बिलासपुर के किस राजा ने राम विलास ग्रंथ की रचना की है – देवी चंद
- वर्ष 2015 के लिए घोषित साहित्य के गद्य पुरस्कार के लिए चयनित उपन्यास डेंजर जोन के लेखक कौन है – बद्री सिंह भाटिया
- मणिकरण कौन सी नदी के किनारे स्थित है – पार्वती
- हिमाचल में फल संग्रहालय कहां खोला जा रहा है – मंडी
- हिमाचल में वनों के तहत कितना क्षेत्र है – 37 हजार 947 हेक्टेयर जो कुल क्षेत्रफल का 68.16 प्रतिशत
- कुल क्षेत्रफल का कितना वन आच्छादित है – 26.4 प्रतिशत
- 2030 तक वनों के तहत वन क्षेत्र को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है – 30 प्रतिशत
- वन समृद्धि जन समृद्धि योजना कहां पर चलाई जा रही है – मंडी, चंबा, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, लाहुल एंड स्पीति, सिरमौर
- हिमाचल प्रदेश फोरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट किसके सहयोग से चलाया जा रहा है – जर्मनी के सहयोग से, यह प्रोजेक्ट चंबा और कांगड़ा में। यह प्रोजेक्ट 2015–16 से 7 साल के लिए चलाया जा रहा है। फंडिंग – 308. 45 करोड़, फंडिंग पैट्रन 85.10 प्रतिशत लोन और 14.90 प्रतिशत
- हिमाचल प्रदेश फोरेस्ट ईको सिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट किसके सहयोग से चलाया जा रहा है – जापान इंटरनेशनल कोओपरेशन एजेंसी
- क्लाइमेट चेंज को लेकर स्टेट नॉलेज सेल कहां पर स्थापित किया गया है – नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन ईको सिस्टम के तहत पर्यावरण, विज्ञान और तकनीकि विभाग शिमला
- क्लाईमेट चेंज वलनरेबिलिटी एसेस्टमेंट किस नदी पर की जा रही है – ब्यास नदी पर
- मॉडल ईको विलेज के तहत कितने गांवों को चयन किया गया है – 11, इन पर 50 लाख प्रति गांव खर्च होगा
- बायो मैथेनेबल प्लांट कहां पर स्थापित किया जाना है – कुफरी, शिमला
- हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर रेशम कीट पालन केंद्र का शिलान्यास किया है – जिला मंडी के बागाचनोगी में
- किस नगर निगम की ओर से आवारा कुत्तों को गोद लेने के बदले फ्री पार्किंग और गारबेज फीस में राहत देने की मुहिम शुरू की गई है – नगर निगम शिमला की ओर से

- यमुना में टोंस नदी निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलती है – कल्सी
- यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर प्रवेश करती है – खाद्य माजरी में

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस सेवा को संकल्प नाम दिया गया है। इस योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 रखा गया है। यह एक टोल फ्री नंबर है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतें इस नंबर पर कर सकता है। जानकारी के मुताबिक संकल्प हेल्पलाइन में लोग अपनी शिकायत सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक दर्ज करवा सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाने और स्टेटस देखने के लिए सेवा संकल्प पोर्टल भी स्थापित किया गया है। इसे हिमाचल सरकार योजना के अंतर्गत कार्य में पारदर्शिता प्रदर्शित होगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का उद्देश्य सभी की समस्याओं को हर संभव तरीको से हल करने की कोशिश करेगी। इसके लिए सॉफ्टवेर उपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर से लगभग 56 विभागों और विभिन्न स्तर के 6500 अधिकारियों को इस जिम्मेदारी को सँभालने का कार्य सौंपा गया है। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि वे संकल्प हेल्पलाइन को हिमाचल के लिए सबसे बेहतर बनाए। शिकायतों को समय रहते समाधान कर दिया जायेगा और लंबित रहने की कोई गुंजाईश का सवाल नही रहेगा। सभी अधिकारियों को सात से चौदह दिन के भीतर लोगों की शिकायतों का निवारण करना आवश्यक होगा। इसके लिए सभी प्रयास मान्य होंगे।

ऑनलाइन शिकायत कैसे करें

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में शुरू हुई मुख्यमंत्री संकल्प योजना का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान करना है।

शिकायतें दर्ज करने के लिए आवेदक टोल फ्री नंबर डायल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ही कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर–1100

अपने फोन के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर डायल कर के भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत क्रमांक लेना न भूलें

इस तरह करें पंजीकरण

- सबसे पहले आपको सेवा संकल्प की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा (http:// cmsankalp.hp.gov.in/)
- आधिकारिक वेबसाइट खुल जाने पर शिकायत, सुझाव दर्ज करें लिंक पर क्लिक करें
- अब ऑनलाइन फॉर्म खुल जायेगा। इस पेज पर आपको अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करना होगा।

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प शिकायत का स्टेटस या स्थिति कैसे जानें

शिकायत या सुझाव दर्ज करने के बाद आप समय समय पर ये जान सकते हैं कि आपकी शिकायत की क्या स्थिति है। स्टेटस ऑनलाइन जानने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या शिकायत क्रमांक होना आवश्यक है।

- सबसे पहले पेज पर जाएँ
- अब शिकायत क्रमांक या मोबाइल नंबर दोनों में से किसी एक का चुनाव करें
- उसके बाद ओटीपी प्राप्त करें और दर्ज कर दें
- आप आपको शिकायत की स्थिति आप जान पाएंगे
- शिकायत सबमिट करने पर शिकायत क्रमांक नोट कर के रख लें

योजना के प्रमुख बिंदु

इस योजना के तहत चार स्तर तक योजना का निवारण हो सकेगा। खंड, तहसील, जिला और राज्य स्तर पर समस्याओं का समाधान हो सकेगा। हर स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए 7 से 14 दिन की अवधि दी जायेगी। हर स्तर पर समस्याओं की निगरानी की जायेगी और हर संभव प्रयास से समस्याओं का समाधान भी अधिकारी द्वारा कर दिया जायेगा। यदि किसी तरह से समस्या का समाधान नही हो पाता है तो वह शिकायत अगले स्तर पर स्थानांतरित कर दी जायेगी। इस 1100 टोल फ्री संकल्प हेल्पलाइन नंबर को सभी के घरों के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। छोटी छोटी समस्याओं के लिये लोगो को दूर दराज क्षेत्र से समस्याएं हल करवाने के लिए मुख्यालय या केंद्रों पर नही आना होगा।

यह योजना प्रभावपूर्ण तरीके से अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी दी जायेगी। इस हिसाब से ही हेल्पलाइन सॉफ्टवेर काम करेगा। इस योजना की निरंतर जाँच की जायेगी और सुझाव नोट किये जायेंगे। सभी सुझावों को इस योजना से मद्देनजर रखते हुए साझा की जायेगी। अधिकारीयों के एक मत से योजना में बदलाव किये जा सकेंगे। डेढ़ साल में हिमाचल सरकार का उद्देश्य 40 हजार शिकायतों का निवारण करने पर होगा। सभी अधिकारी इस योजना के लिए तत्परता से काम में जुटे हैं और लोगो को उनकी समस्याएं सुलझाने में सहायता प्रदान करेंगे।

जरूरी लिंक्स

- सेवा संकल्प आधिकारिक वेबसाइट
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें
- शिकायत का स्टेटस देखें

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित को शिकायत नहीं माना जायेगा

- माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण
- अन्य राज्य, केंद्र, विदेशी सरकार के खिलाफ शिकायत
- विभागीय पूछताछ सम्बंधित, अधिकारियों के स्थानांतरण सम्बन्धी मामले,सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामले।
- सूचना का अधिकार से सम्बंधित मामले

वन समृद्धि–जन समृद्धि योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आबादी की आमदनी बढ़ाने के लिए वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना शुरू की है। इस योजना के जरिये ग्रामीण लोग औषधीय पौधे की खेती कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। सरकार राज्य में उगने वाले करीब 3400 औषधीय पौधे की खेती के लिए लोगों को वित्तीय मदद के रूप में 25 प्रतिशत तक सब्सिडी भी देगी। क्या है वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना और क्या है इसके का उदेश्य? इस बारे में हम द रीव टाइम्स के इस अंक के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बहुमूल्य जड़ी बूटियों को संरक्षित और सुरक्षित करना है। इलाज और दवाई बनाने में काम आने वाले औषधीय पौधे की खेती आसानी से की जा सकती है। सरकार इसके लिए ग्रामीणों को बीज समेत तमाम मदद उपलब्ध कराएगी और उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से इनकी बाजार कीमत पर बिक्री की व्यवस्था करेगी। इस योजना के माध्यम से सरकार उन औषधीय पौधे का संरक्षण भी कर सकेगी जो धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं।

योजना की मुख्य बातें

हिमाचल सरकार वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के माध्यम से उन ग्रामीण परिवारों की आर्थिक आय बढ़ाने के प्रयास कर रही है जो औषधीय पौधे की खेती में जुटे हैं। सरकार फसल तैयार होने के बाद कटाई, मूल्य वृद्धि और उसके विपणन पर ध्यान देगी। ग्रामीण अपनी जमीन पर औषधीय पौधे उगा सकते हैं, इसके लिए राज्य सरकार उन्हें 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। जब औषधीय पौधे, बीज, फूल, पत्तियां तैयार हो जायेंगे तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से इसकी बिक्री की जाएगी। इन चिकित्सीय उत्पाद को उस विशेष जड़ी बूटी के बाजार मूल्य पर खरीदा जाएगा। खेत या जंगल से इस तरह की जड़ी-बूटियों की बिक्री अवैध तरीके से नहीं की जा सकेगी। हिमाचल सरकार वास्तव में राज्य के जंगल-खेतों में उगाए जाने वाले औषधीय पौधे की किसानों को उचित कीमत दिलाना चाहती है। अब तक इस तरह के उत्पादों का कोई खास बाजार नहीं है और इस वजह से औषधीय पौधे की खेती से किसान को विशेष लाभ नहीं हो पता। हिमाचल सरकार इस समय प्रदेश के उन 5 जिलों में मैपिंग कर रही है जहां ऐसे औषधीय पौधे पाए जाते हैं। सरकार की कोशिश यह है कि इन इलाके के किसानों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराया जाय और चिकित्सीय पौधे का उत्पादन बढ़ाया जाय।

- औषधीय पौधे की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। सरकार की यह योजना जड़ी बूटियों के संरक्षण में लाभदायक सिद्ध होगी।

वन समृद्धि जन समृद्धि योजना में स्वंय सहायता समूहो को प्रशिक्षण

हिमाचल सरकार का वन विभाग जंगल से जड़ी-बूटी निकालने व चुनने और पहचान के लिए स्व-सहायता समूह को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें जड़ी बूटी निकालने के तरीके और उसके लिए उपयुक्त समय के बारे में जानकारी दी जा रही है। औषधीय पौधे की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार 25 प्रतिशत तक (10,000 रुपये) सब्सिडी देने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने औषधीय पौधे की खेती पर सब्सिडी के लिए एक कॉर्पस फंड भी बनाया है।

किस तरह के औषधीय पौधे हैं राज्य में?

औषधीय पौधों के माध्यम से चिकित्सा उपचार के लिए हिमाचल प्रदेश को देश के सबसे बेहतर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में जंगल हैं जहां विविध प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है। इनमें सताव, औंरा, बंदरा, काली तुलसी, वन बैगन, सिकटी, हर्रे, घृत कुमारी, पीपर, नीम, सफेद मुसली, सर्पगंधा, मीठा नीम, हरला-वाकस, जंगली (लाल) प्याज, रीठा, सीता पत्ता, मैदा वृक्ष, गुड़माड़ वृक्ष, बेलपत्र, इंदुजा, राम दतवन, धतुरा, कैकटस, सफेद पलास, काली हरदी, सफेद चंदन, दुधी लता, बहेड़ा, सोमराज, वायडींग, पुनर्नवा, ब्राम्ही, चाल जैसे औषधीय पेड़-पौधों सहित जड़ी-बूटियां शामिल हैं। हिमाचल वन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जंगल में औषधीय पौधों की करीब 1038 प्रजातियां हैं जिनसे 3,400 प्रकार की अमूल्य जड़ी-बूटियां मिलती हैं। हिमाचल प्रदेश वन समृद्धि जन समृद्धि योजना इन अनमोल जड़ी बूटियों के संरक्षण और सुरक्षा में मदद करेगी। हिमाचल सरकार कैंपा फंड के जरिये अगले तीन साल में प्रदेश भर में 22 वन विहार-ईको पार्क स्थापित करेगी। इन इलाके में भी औषधीय पौधे की खेती की जा सकेगी। वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के जरिये जड़ी बूटी इकट्ठा करने, प्रसंस्करण और विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना (हिम केयर)

जनवरी माह में बनेगें हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड (हिम केयर)

हिमाचल में लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसी ही एक योजना है हिम केयर। इस योजना के तहत मात्र एक हजार रूपये सालाना का प्रीमियम देकर सरकारी अस्पतालों में पांच लाख तक का ईलाज निशुल्क करवाया जा सकता है। द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विशेष तौर पर शुरू की गई हिम केयर योजना की जानकारी देने जा रहे हैं।

हिम केयर योजना क्या है?

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुफ्त कैशलेस उपचार प्रदान करेगी। इस योजना को संक्षेप में 'हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना' या हिम केयर कहा जाता है। यह योजना दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी। यह योजना हिमाचल के निवासियों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई है। खास बात यह कि इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकते हैं जो आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं किए जा रहे हैं। इन दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता।

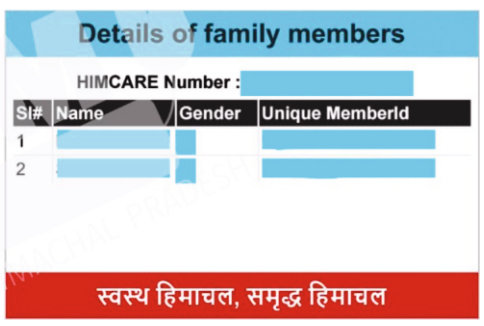

हिम केयर योजना के लाभ

चयनित परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक निशुल्क इलाज का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत एक कार्ड पर अधिकतम पांच सदस्यों को लाभ मिलेगा। अगर किसी परिवार में सदस्यों की संख्या पांच से अधिक है तो ऐसे परिवारों के दो कार्ड बनाएं जाएंगे।

इस स्कीम में लगभग 1800 उपचार प्रक्रियाओं कवर की जा रही है इसमें डे -केयर सर्जरी भी शामिल है।

परिवार के सभी सदस्य इस योजना के तहत शामिल होने के पात्र है। इसमें कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गयी है।

193 अस्पताल हैं लाभ देने के लिए पंजीकृत

प्रदेश में 193 अस्पताल पंजीकृत हैं, जिनमें लाभार्थी निशुल्क इलाज प्राप्त कर सकते हैं।

हिम केयर योजना के तहत प्रीमियम

साधारण तौर पर इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 1000 रूपये सालाना प्रीमियम देना होता है। लेकिन इसमे समाज के कुछ विशेष वर्गों को प्रीमियम चुकाने में छूट दी गई है। इसके लिए तीन श्रेणियां बनाई गई । पहली श्रेणी में कोई प्रीमियम नहीं है जबकि दूसरी श्रेणी में प्रतिदिन एक रूपये प्रीमियम के हिसाब से सालाना 365 प्रीमियम है जबकि तीसरी श्रेणी में 1000 रूपये प्रीमियम चुकाकर ई कार्ड बन जाता है और इस कार्ड के आधार पर एक साल के लिए पांच लाख तक का इलाज निशुल्क करवाया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि इलाज उन्हीं अस्पतालों में करवाया जाए जिन्हें सरकार द्वारा पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत अस्पतालों की सूची हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी की अधिकारिक वेबसाईट https://hpsbys.in/content/mmmn पर उपलब्ध है

प्रथम श्रेणी -बीपीएल और पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर (जो आयुष्मान भारत के तहत कवर नहीं होते)

दूसरी श्रेणी

विकलांग -पहले इस योजना के तहत उन विकलांगों को ही शामिल किया जाना था जिनकी विकलांगता 70 प्रतिशत या इससे अधिक हो लेकिन अब 40 प्रतिशत विकलांगता को भी कवर करने का प्रावधान किया जा रहा है।

वरिष्ठ नागरिक- 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक (वर्तमान में 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक कवर किए गए हैं और नई योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कवर करने का प्रस्ताव है)

-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा कार्यकर्ता (जो किसी अन्य स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले रहे), मिड-डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी (स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदि)। पार्ट टाइम वर्कर्स (सरकार, स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदि) , संविदा कर्मचारी (सरकारी, स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदि)

तृतीय श्रेणी

जिन लाभार्थियों को श्रेणी- । और श्रेणी- ॥ के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है या जो किसी सरकारी नौकरी में नहीं और परिवार में किसी पर आश्रित नहीं है।

हिम केयर के लिए नामांकन कैसे करें?

हिमाचल प्रदेश के निवासी www-hpsbys-पद वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यह वेब इंटरफेस राशन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी के प्रमाण को कैप्चर करेगा।

लाभार्थी या तो सीधे ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से या लोक मित्र केंद्र (LMK) कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। निवासी ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं।

लाभार्थियों को एक नामांकन प्राप्त होगा जब उनके नामांकन को पीछे से मंजूरी दी जाती है और वह हिम केयर के तहत जारी किए गए अपने ई-कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

ई - कार्ड डाउनलोडिंग लिंक लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उपलब्ध होगा। ये ई -कार्ड अस्पताल स्तर पर भी उत्पन्न किए जा सकते हैं।

दस्तावेजों के नामांकन और अपलोड के लिए प्रत्येक परिवार द्वारा 50 का भुगतान करना होगा।

ई कार्ड की छपाई रु। के इस शुल्क में सम्मिलित होगी।

50. लाभार्थी इस मुद्रित कार्ड को संबंधित सीएससी, एलएमके से अपना नामांकन अनुमोदन संदेश प्राप्त करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण नोट

हिम केयर योजना में मुखिया राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना (MMSHCS) और हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (HPUHPS) शामिल होंगी। इन दो योजनाओं के तहत सभी मौजूदा लाभार्थियों को एक ही यूनिक आईडी के साथ अपना सारा डेटा नई प्रणाली पर उपलब्ध होगा।

हिम केयर नामांकन स्थिति की जांच कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा

योजना सोसाइटी (HPSBYS) पर विजिट करें:

'हिम केयर एनरोलमेंट' टैब पर क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा। दिखाई देने वाले ड्रॉप डाउन में से 'हिम केयर एनरोलमेंट स्टेटस' पर क्लिक करें।

संदर्भ संख्या, राशन कार्ड नंबर पूछने वाला पृष्ठ दिखाई देगा।

उसे भरें और एंटर दबाएं। आपकी नामांकन स्थिति प्रदर्शित की जाएगी।

पुराने कार्ड को हिम केयर पर कैसे बदले?

HPSBYS वेबसाइट के होम पेज पर जाएं।

'हिम केयर एनरोलमेंट' टैब पर क्लिक करें, एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देगा।

माइग्रेट पुराने कार्ड से 'हिम केयर' लिंक पर क्लिक करें।

आपका URN नंबर मांगने वाला एक पेज दिखाई देगा, इसे भरें और आगे आने वाले निर्देशों का पालन करें।

हिम केयर कार्ड का नवीनीकरण कैसे करें?

संबंधित लाभार्थी को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उनकी पॉलिसी नवीनीकरण तिथि के बारे में सूचित किया जाएगा। वे अपनी संबंधित पॉलिसी को नवीनीकृत करने के लिए 15 दिन पहले एक पॉलिसी नवीनीकरण लिंक प्राप्त करेंगे।

कार्ड का नवीनीकरण कैसे करें

वेबसाइट पर, सीधे 'हिम केयर' टैब पर जाएं।

'कार्ड के नवीनीकरण' लिंक पर क्लिक करें।

अपना URN / Himcare नंबर दर्ज करें और उन निर्देशों का पालन करें जो दिखाई देंगे।

आगामी जनवरी माह से बनेगे नए कार्ड: विपिन परमार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ महत्त्वाकांक्षी हिमकेयर योजना के तहत नए कार्ड आगामी जनवरी माह से बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमकेयर के तहत अब तक 5.50 लाख परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका है तथा एक वर्ष पुराने कार्डों का नवीनीकरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो परिवार आयुष्मान भारत योजना से वंचित रह गए उनके लिए हिमकेयर योजना आरम्भ की गई है जिसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने पर लाभार्थियों को पांच लाख रुपए के निःशुल्क उपचार की सुविधा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अब तक हिमकेयर योजना के अंतर्गत 47,882 लाभार्थियों को 46.25 करोड़ रुपए से अधिक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाया जा चुका है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

बागवानों के घर द्वार पहुंचा मिशन रीव

मिशन रीव के तहत सेब बागवानों को सेब की खेती के बारे में जानकारी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सेब के बागीचों में जाकर बागवानों से बात की जा रही है और उन्हें वैज्ञानिक ढंग से बागवानी करने के बारे में जानकारी दी जा रही है। मिशन रीव के तहत दी जा रही विभिन्न सेवाओं के बारे में बताने के साथ ही बागवानों की समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर उनका निवारण भी किया जा रहा है। मिशन रीव प्रतिनिधि पंकज ने बताया कि बागवानों से सीधे संपर्क स्थापित कर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

हाल ही में रामपुर में प्रूनिंग कैंप के दौरान अंकुश, प्रमोद ठाकुर, जिया लाल और पंकज चौहान ने बागवानों को जागरूक किया। इसके साथ ही किन्नौर के पिओ में धीरज, योगराज धर्मेंद्र और पंकज चौहान ने भाग लिया। इसी तरह रोहड़ू के अढहाल में भी बागवानों को जागरूक किया। यहां पर मिशन रीव प्रतिनिधि और पेशे से बागवान पंकज ने बागवानों को सेब उत्पादन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इन जागरूकता शिविरों में भाग लेने वाले किसानों ने बताया कि मिशन रीव के तहत महत्वपूर्ण जानकारी बागवानों को उपलब्ध करवाई जा रही है। सेब की कलम करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फूलावरिंग के वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आदि कई महत्वपूर्ण जानकारी बागवानों को दी जा रही है।

द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कुछ नामी बागवानों से बातचीत पर आधारित सुझाव और तरीके जैसे कि सेब की खेती करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सेब के क्या क्या फायदे हैं। हिमाचल में सेब उत्पादन का राजस्व में एक बड़ा योगदान है। यहां की आर्थिकी का बड़ा हिस्सा सेब बागानों से पूरा होता है। इसके अलावा सेब सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है।

पोषक तत्व व उपयोग

सेब के बारे में कहा जाता है कि 'एन एप्पल ए डे कीप्स द डाक्टर अवे'। मतलब रोज एक सेब खाने से आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती। आईआरडी रीव क्लीनिक के एचओडी डाक्टर केआर शांडिल के मुताबिक सेब विटामिन बी, विटामिन सी व खनिज लवणों से भरपूर है। यह फल हृदय,मस्तिष्क व जिगर के रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। सेब को फल के रूप में खाने के अलावा चटनी, मुरब्बा, जैम, जेली, अचार आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है ।

सेब एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। देश में इसकी बागवानी समुद्र तल से 1800 – 2700 मीटर ऊंचाई तक की जाती है। 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी बागवानी से अधिकतम उपज प्राप्त की जाती है। सेब के पेड़ को समुचित विकास व पुष्पन व फलन के लिए न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है।

भूमि का चयन

सेब की बागवानी के लिए उचित जल निकास वाली क्ले दोमट भूमि उपयुक्त रहती है। सेब के पौधों के उचित विकास व बढ़वार के लिए थोड़ी अम्लीय व गहरी होनी चाहिए।

सेब का प्रवर्धन

हमारे देश में प्रवर्धन की कई विधियाँ है किंतु सेब का प्रवर्धन दो विधियों से ही किया जाता है

- कलम लगाकर
- चश्मा लगाकर
- कलम लगाकर सेब के पौधे तैयार करना

चश्मा बांधने अथवा कलम लगाने के लिए किसान भाई एक वर्षीय पौधे का चुनाव करें। सेब की कलम लगाने के लिए फरवरी-मार्च का समय उपयुक्त होता है। 40 से 85 सेंटीमीटर की दूरी पर कलम लगाने के लिए उगाए जाने वाले पौधों की क्यारियों में आपस की दूरी रखें। सितम्बर महीने में चश्मा बांधना अच्छा रहता है। व्यवसायिक बागवानी के लिए चश्मा बांधकर सेब के पौधे तैयार करना लाभकारी होता है।

सेब से पौधे लगाना

सेब लगाने के लिए 90×90 सेंटीमीटर गहरे व व्यास के 6 से 7 मीटर की दूरी में गड्ढे खोद लेने चाहिए। 15 से 18 किलोग्राम प्रति गड्ढा सड़ी गोबर की खाद व मिट्टी भरकर माह भर छोड़ देना चाहिए। पौधों को फंफूदजनित रोगों से बचाने के लिए 150 ग्राम एल्ड्रिन धूल 10 प्रतिशत भी मिट्टी में मिला दें। रोपाई के पहले तैयार पौधों की जड़ों को फफूंदनाशी एगलाल, थायरम, अथवा कैप्टान से उपचारित कर लेना चाहिए।

शाम के समय अथवा ठंडे मौसम में सेब से पौधे गड्ढे के बीचोबीच रोपना चाहिए। गड्ढे के खाली ऊपरी जगह को मिट्टी से भर दें तथा पौधे के चारों ओर तौलिए बना दें। पौधे की ओर ऊंचाई बनाते हुए मिट्टी चढ़ा दें। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। ध्यान रहे पानी पौधे के तने के संपर्क में न आये अन्यथा जड़ सड़न,तना सड़न रोग आदि का खतरा पनप सकता है।

खाद व उर्वरक

सेब में मानकों के मुताबिक खाद व उर्वरक देना चाहिए। खाद को फावड़े के द्वारा मिटटी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। फॉस्फोरस को 10 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिये।

पौधे की देखभाल, निराई – गुड़ाई व खरपतवार नियंत्रण

सेब के पौधे सीधे रहे इसके लिए आरम्भ में भी लकड़ी के सहारे स्टेपनी से बांध दें। थालों में उगी घास खरपतवारों को नियमित रूप से निराई गुड़ाई कर निकाल दें। एक अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गए रिसर्च के परिणाम के अनुसार थालों को पत्तियों से ढकने पर अधिक उपज प्राप्त होती है।

आम के बाग में लगने वाले कीटों व रोगों की रोकथाम के उपाय

सिंचाई व जल प्रबंधन : सेब के पौधों में बसन्त काल व ग्रीष्मकाल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। 7 से 10 दिन के अंतर नियमित रूप से सिंचाई करना चाहिए। वैसे सेब 60 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में एक बार पौधा लग जाने पर सिंचाई की न में बराबर ही आवश्यकता होती है ।

सेब के पौधे की कटाई छँटाई

सेब के पेड़ से अच्छा फलन लेने के लिए सेब के पेड़ का आकार सही होना अति आवश्यक है। इसके लिए शुरुआत से प्रयास करना शूरू कर देना चाहिए ।सेब के पेड़ को आकार देने के लिए मोडिफाइड लीडर विधि उत्तम मानी जाती है। सेब का पेड़ लग जाने के बाद उसे 70 से 85 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट देना चाहिए। इस विधि के अनुसार पेड़ का मुख्य तने को छोड़कर उसके चारों ओर से 6 से 8 शाखाओं के चुनाव कर लेना चाहिए। ध्यान रहे एक शाखा से दूसरी शाखा के मध्य 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में 3 से 4 साल तक लग जाते हैं। जब सभी शाखाएं विकसित हो जाएं मुख्य शाखा को तने से काट कर अलग कर दें बस इतना ध्यान दें कि वह तने से सटी हुई न हो। जब भी छँटाई करें इन शाखाओं के सिरे न निकालें। सेब के पेड़ की कटाई छँटाई करते समय कटाई हमेशा पेड़ के ऊपरी भाग से आरम्भ कर भीतरी भाग की तरफ करें। छंटाई करते समय रोग ग्रसित व सूखी टहनियों को भी काटें। अधिक घनी शाखाओं को भी काटें। कटाई छँटाई का काम जाड़ों में करें।

पुष्पन व फलन के समय देखभाल

सेब में पुष्पन फरवरी-मार्च में होता है। साथ ही विभिन्न किस्मों के अनुसारअगस्त से अक्टूबर तक सेब के फल पकने लगते हैं। सेब के फल समय से पहले न गिरे इसके लिए थालों में पर्याप्त नमी रखना चाहिये। साथ ही बोरान व मैग्नीशियम की समुचित मात्रा देनी चाहिए। विषेशज्ञों की मानें तो फलों के शीघ्र गिराव रोकने में लिए अल्फा नेफ्थलीन एसिड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।

सेब के फलों की तुड़ाई

जैसे ही फल पूर्ण विकसित,सुड़ौल व परिपक्व हो जाये। बिना विलम्ब किये फलों को डंठल सहित तोड़ें। साथ ही ध्यान रखें कि फल तोड़ते समय चोटिल न हों।

फलों का भंडारण

सेब के फलों को शीत गृह में 0 डिग्री सेल्सियस से 1.70 डिग्री सेल्सियस तापमान में भंडारित कर दें ।

द रीव टाइम्स

संस्थापक: डॉ एल.सी. शर्मा

प्रकाशक: आईआईआरडी काम्पलेक्स, बाईपास रोड शनान, सन्जौली शिमला-6 हि.प्र.

द रीव टाइम्स के लिए मुद्रक प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस, सायबू निवास समीप सेक्टर-2, बस स्टैंड, मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित

संपादक: हेम राज चौहान

फोन न. : 0177 2640761
आर.एन.आई. रिफ्रेंस नं. 1328500
टाइटल कोड : HPBIL00313
पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं. HP/129/SML/2019-2021

E-mail : hem.raj@iirdshimla.org
Website : www.therievtimes.com

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के / लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

दूरभाष : 9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़..... द रीव टाइम्स उत्कृष्ठ गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर – द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट ीजजचरुध्ध्नइण्उपेपवदतपमअण्पद पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता / अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500 रूपये, छः माह के लिए 250 रूपये में और घर बैठे पांऐ द रीव टाइम्स..... क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र